सांध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

वर्ष–01 अंक–186 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शनिवार 25 जुलाई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

सु-विचार

" सांप सीढ़ी बचपन का नहीं पूरी जिंदगी का खेल है
फर्क बस इतना है कि जिंदगी में पासे नहीं लोग पलटते हैं...!! "
अज्ञात...

SAIL ने Q1 FY27 में दर्ज किया शानदार मुनाफा, शुद्ध लाभ 138% बढ़कर 1636 करोड़

EBITDA 48% की बढ़ोतरी, सीएमडी डॉ. अशोक कुमार पंडा : घरेलू मांग से आगे भी मजबूत रहेगा प्रदर्शन

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड रअक्छ ने वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी ने 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही में मजबूत लाभ कमाया है। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में शुद्ध लाभ में 138% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

मुनाफा बढ़ा, उत्पादन थोड़ा घटा

रअक्छ का कर–पश्चात लाभ ढअळ द1 ऋ27 में 1636 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल द1 ऋ26 के 685 करोड़ रुपये की तुलना में 138% अधिक है। एइक्ळउ्अ भी 48% बढ़कर 4356 करोड़ रुपये रहा।

वहीं भू–राजनीतिक तनाव के कारण सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए कंपनी ने अपनी मरम्मत और मेंटेनेंस का कुछ काम समय से पहले निपटा लिया। इसके चलते इस तिमाही में कच्चा इस्पात उत्पादन 4.76 मिलियन टन और विक्रय मात्रा 4.16 मिलियन टन रही, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम है। कंपनी का कहना है कि इस अग्रिम तैयारी से आने वाली तिमाहियों में उत्पादन अधिक स्थिर रहेगा और प्रदर्शन बेहतर होगा।

सीएमडी ने जताया भरोसा

रअक्छ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. अशोक कुमार पंडा ने कहा, दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद देश में स्टील की लगातार बढ़ती मांग के कारण भारतीय स्टील इंडस्ट्री मजबूती से टिकी रही। सेल ने कामकाज को बेहतर बनाकर, खर्चों को नियंत्रित करके और सही मार्केटिंग रणनीति से इस तिमाही में बड़ा मुनाफा कमाया है।

उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अपनी मजबूत विनिर्माण क्षमताओं का पूरा लाभ उठाएगी और घरेलू स्टील की बढ़ती मांग के साथ अपने प्रदर्शन को और मजबूत करना जारी रखेगी।

Q1 FY27 के प्रमुख आंकड़े :

विवरण	इकाई	Q1 25–26	Q4 25–26	Q1 26–27
कच्चा इस्पात उत्पादन	मिलियन टन	4.85	5.08	4.76
विक्रय मात्रा	मिलियन टन	4.55	5.32	4.16
प्रचालन से कारोबार	रुपया करोड़	25,921	30,813	26,246
EBITDA	रुपया करोड़	2,925	4,762	4,356
PBT	रुपया करोड़	890	2,324	2,159
PAT	रुपया करोड़	685	1,680	1,636

विश्लेषण

फास्ट ट्रैक कोर्ट से थमेगा पेपर लीक या सिर्फ कागजी दावा?

आलोक तिवारी/ नईदिल्ली

पेपर लीक माफिया पर लगाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' और कड़े कानून बनाने का ऐलान किया है। मध्यप्रदेश ने 4 और बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 विशेष अदालतें बनाने का फैसला भी ले लिया है। लेकिन सवाल वही है – क्या अदालत के नाम में 'फास्ट' जोड़ देने से 23 साल से चल रहा पेपर लीक का खेल खत्म हो जाएगा? आंकड़े बताते हैं कि हकीकत उतनी आसान नहीं है।

आंकड़े: सजा की रफ्तार रेंगती हुई : पिछले 23 सालों का रिकॉर्ड पेपर लीक के खिलाफ सिस्टम की नाकामी की कहानी कहता है : 3 .86 करोड़ युवा प्रभावित 45 बड़े पेपर लीक की घटनाओं से लगभग 3 करोड़ 86 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा। 1600+ गिरफ्तारी, आधी चाजर्शीट भी नहीं* : कुल 1,658 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन जांच एजेंसियां सिर्फ 925 के खिलाफ ही चाजर्शीट दाखिल कर पाईं। सजा न के बराबर 45 मामलों में से 43 में आज तक फैसला नहीं आया। सिर्फ 2 मामलों में 18 लोगों को सजा मिली। **हिसाब:** यानी हर 21 लाख प्रभावित छात्रों पर केवल 1 दोषी को सजा। परीक्षा रद्द करने और दोबारा कराने में सिस्टम तेज है, पर दोषियों को जेल पहुंचाने में उतना ही सुस्त।

केस स्टडी: 'फास्ट ट्रैक' की धीमी हकीकत : तीन मामले सिस्टम की जमीनी सच्चाई उजागर करते हैं : **23 साल बाद फैसला:** 2002 का रेलवे भर्ती लीक। आरोपी आरपीएफ जवान था। सीबीआई जांच के बाद फैसला आने में 23 साल लगे। **2 दिन में जमानत:** 2010 का रेलवे भर्ती बोर्ड चेयरमैन केस। 14 साल बाद जनवरी 2024 में सजा, पर ऊपरी अदालत से 2 दिन में जमानत। **18 साल से तारीख पर तारीख:** 2006 का रेलवे ग्रुप डी लीक। 142 से ज्यादा सुनवाई हो चुकीं, फैसला अब भी बाकी। इस बीच कुछ आरोपी विधायक तक बन गए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के रास्ते की 3 सबसे बड़ी रुकावटें : पहली रुकावट – सुस्त जांच* : कोर्ट तभी दौड़ेगा जब पुलिस/सीबीआई चाजर्शीट देगी। जब जांच एजेंसियां 1600 में से 700 मामलों में चाजर्शीट ही नहीं दे पाईं, तो कोर्ट कितना भी तेज हो क्या करेगा? **दूसरी रुकावट – जजों की भारी कमी:** निचली अदालतों में हर 5 में से 1 जज का पद खाली है। पहले से 3 .6 करोड़ केस पेंडिंग हैं। नए केसों के लिए जज, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा? **तीसरी रुकावट – अधिकार का पेच:** संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना और जजों की नियुक्ति राज्य सरकार और हाईकोर्ट का काम है। केंद्र सीधे दखल नहीं दे सकता। यानी घोषणा केंद्र की, अमल राज्यों पर।

छात्रों का असली सवाल: न्याय या सिर्फ सजा ? : कानून सख्त करना जरूरी है, पर छात्रों के लिए इससे बड़ा सवाल है – बर्बाद हुए सालों का क्या? पेपर लीक के बाद छात्र 2 बार परीक्षा देते हैं, फीस और समय दोनों गंवाते हैं। कई की उम्र सीमा निकल जाती है। विश्लेषकों का मानना है जब तक सिस्टम ये 3 गारंटी नहीं देता, तब तक न्याय अधूरा रहेगा। **उम्र में छूट:** लीक के कारण देरी हुई तो एज लिमिट में रियायत। समयबद्ध दोबारा परीक्षा : 90 दिन के अंदर पारदर्शी री–एग्जाम की कानूनी गारंटी। **मुआवजा:** आर्थिक नुकसान और मानसिक पीड़ा की भरपाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक जरूरी कदम है, लेकिन रामबाण नहीं। जब तक जांच एजेंसियां तेज नहीं होंगी, जजों की कमी पूरी नहीं होगी और पीड़ित छात्रों को राहत नहीं मिलेगी, तब तक पेपर लीक माफिया के हौसले पस्त नहीं होंगे।

अदालत का नाम बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था बदलने के लिए जांच से लेकर सजा और पीड़ित को राहत तक – हर कड़ी को फास्ट ट्रैक करना होगा। वरना ये भी बाकी घोषणाओं की तरह सिर्फ कागजी दावा बनकर रह जाएगा।

प्रधान के इस्तीफे पर आज संभव चर्चा छात्रों पर से केस हटाने पर बनी सहमति

सरकार–CJP वार्ता का दूसरा दौर, जंतर–मंतर पर हाई–टेक निगरानी, सोशल मीडिया पर अफवाहों का हमला

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर केंद्र सरकार का रुख 48 घंटे में बदला है। शुक्रवार को सरकार और CJP के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि CJP ने 3 मुख्य मांगें और परीक्षा सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। सरकार इन पर चर्चा कर रही है। अगली बैठक शनिवार दोपहर को होगी।

क्या मांगी सीजेपी ने

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका के अनुसार संगठन ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई समझौता नहीं करने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने इस पर विचार के लिए शनिवार दोपहर 3:30 बजे तक का समय मांगा है। इसके अलावा सीजेपी ने पेपर लीक के कारण सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को 1–1 करोड़ रुपये मुआवजा देने और आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग रखी। प्रवक्ताओं ने कहा कि इन दो मांगों पर सरकार ने सैद्धांतिक सहमति जताई है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

एनटीए और परीक्षा सुधार पर सरकार के कदम

संसद में दी जानकारी के अनुसार एनटीए में स्वीकृत 39 स्थायी पदों में से केवल 24 पर ही अधिकारी हैं, 15 पद खाली हैं। कामकाज के लिए 73 संविदा और 124 आउटसोर्स कमर्चारी तैनात हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बताया कि एनटीए को मजबूत करने के लिए निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के 16 नए पद सृजित किए गए हैं। लगातार विवादों के बीच मंत्रालय में दो अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय भेजा गया है।

पीएम मोदी की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश ने 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर–छत्रपति संभाजीनगर में 2 विशेष अदालतें बनाने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच में एसटीएफ भी गठित की है।

जंतर–मंतर: तनाव के बीच हाई–टेक सुरक्षा

प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने चार फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए हैं जो सीधे पुलिस डेटाबेस से जुड़े हैं। भीड़ में फरार आरोपी दिखते ही अलर्ट जारी हो रहा है। मेट्रो के 15 स्टेशन सुरक्षा कारणों से लगातार तीसरे दिन बंद रहे। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। सीजेपी ने 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई में शामिल कर्मियों की पहचान के लिए वेबसाइट लॉन्च करने का ऐलान किया है। संगठन ने प्रदर्शनकारियों से फोटो–वीडियो मांगे हैं।

राहुल का आरोप, पुलिस का इनकार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 जुलाई के प्रदर्शन में घायल छात्र साहिल को सामने लाकर दावा किया कि उस पर पेलेट गन चलाई गई। दिल्ली पुलिस ने पेलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है। सूत्रों के अनुसार सीआरपीएफ इसकी जांच कर रही है।

सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर

पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि घायल 21 वर्षीय युवती को मृत बताकर एक्स पर पोस्ट की गई। जांच में यह दावा फर्जी निकला। महिला का इलाज जारी है और वह अब खुद सांस ले रही है। पीआईबी के अनुसार 400 से अधिक संदिग्ध पाकिस्तानी अकाउंट्स से भ्रामक सामग्री फैलाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी तरह सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके की मौत की वायरल खबर को भी पुलिस ने फर्जी बताया है। पुलिस ने कहा दीपके पूरी तरह स्वस्थ हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक मामले को ऐसे ही नहीं चलने दिया जा सकता। सरकार से ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी पर सवाल पूछा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा सरकार 10 कदम आगे काम कर रही है। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि छात्रों की याचिका पर सुनवाई से इनकार नहीं किया गया था, अदालत में सिर्फ पत्र मिला था। कोर्ट ने बिना अनुमति कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर भी रोक लगाई। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक तीन दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उनका ब्लड शुगर 66 तक गिर गया है। उन्होंने भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जेएनयू और डीयू ने छात्रों को एडवायजरी जारी कर प्रदर्शन स्थल से दूर रहने और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से पोस्ट करने को कहा है। सीजेपी का प्रदर्शन 20 जून से जारी है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक जारी रहेगा।

जेल की चारदीवारी के बीच सात फेरे, कैदी बना दूल्हा, बलात्कार मामले में सजा काट रहा कैदी

न्यायालय की अनुमति से रचाई शादी, जेल प्रशासन और अधिवक्ता बने घराती–बाराती

नई दृष्टिबिंदु / जगदलपुर

एक ऐसी शादी आज जगदलपुर के केंद्रीय जेल में संपन्न हुई जहां जेल प्रबंधन और अधिवक्ता ही घराती और बाराती बने। सजा काट रहे एक कैदी ने जेल परिसर में ही रीति–रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ अपनी प्रेमिका से सात फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंध गया।

जानकारी के अनुसार बलात्कार के एक मामले में पिछले 7 माह से केंद्रीय जेल जगदलपुर में सजा काट रहे कैदी ने जेल प्रबंधन के सामने अपनी प्रेमिका से शादी करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद कैदी और युवती दोनों ने शादी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जेल प्रशासन ने इस संबंध में माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी। न्यायालय ने दोनों के आवेदन को स्वीकार करते हुए जेल प्रबंधन को जेल नियमों का पालन करते हुए शादी संपन्न कराने के आदेश दिए।

न्यायालय के आदेश के बाद जेल प्रशासन ने जेल परिसर में भव्य मंडप सजाया। कैदी को दूल्हे के रूप में तैयार किया गया। इसके बाद परिजनों, अधिवक्ताओं और जेल प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में दोनों ने पूरे विधि–विधान से विवाह किया। शादी के दौरान मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने एक–दूसरे को वरमाला पहनाई और सात फेरे लिए। शादी समारोह में मौजूद सभी लोगों ने नवविवाहित जोड़े को सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। जेल अधीक्षक ने बताया कि यह शादी पूरी तरह जेल नियमों के तहत और न्यायालय के निर्देश पर कराई गई है।

EBIX कंपनी के मालिक विकास गर्ग 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए

10 दिन की एऊरिमांड में महादेव सट्टा कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मिले सुबूत

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार एइक कंपनी के मालिक विकास गर्ग को बुधवार को PMLA की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद विकास गर्ग को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

ईडी ने 10 दिन की पूछताछ के दौरान विकास गर्ग से महादेव ऑनलाइन सट्टे की काली कमाई को सफेद करने से जुड़े कई अहम खुलासे कराए हैं। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में विकास गर्ग ने कई बड़े नामों का जिक्र किया है।

महादेव सट्टा संचालकों से गहरे संबंध

ईडी के अनुसार जांच में विकास गर्ग के महादेव ऑनलाइन सट्टा के संचालक सौरभ चंद्राकर से घनिष्ठ संबंध होने के सुबूत मिले हैं। इसके अलावा सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और दोनों की पत्नियों के बैंक खातों में रकम जमा करवाने के प्रमाण भी मिले हैं।

एजेंसी का आरोप है कि महादेव ऑनलाइन सट्टे से आई काली रकम को विकास गर्ग और उनके सहयोगियों ने अपनी कंपनियों के जरिए वाइट मनी में कनवर्ट किया। इस संबंध में ईडी को पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं।

कई लोगों को भेजे गए नोटिस

पूछताछ में सामने आए नामों के आधार पर ईडी ने PMLA की धारा 50 के तहत कई लोगों को नोटिस जारी किए हैं।

सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनकी पत्नियों के खातों में रकम जमा कराने के प्रमाण

अधिकारियों का कहना है कि आगे की पूछताछ में और खुलासे होने पर और गिरफ्तारी की संभावना है।

कोर्ट परिसर में हंगामा

विकास गर्ग को पेशी के लिए लाते समय उनके सहयोगियों ने तौलिया से मीडिया के कैमरे छिपाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ लोगों ने मीडिया कमिर्यो से कोर्ट परिसर में बदसलूकी भी की।

गौरतलब है कि ईडी महादेव ऑनलाइन सट्टा एप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पहले भी कई राज्यों में छापेमारी और गिरफ्तारी हो चुकी हैं। अब विकास गर्ग से मिली जानकारी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।

चरोदा में मिला दुर्लभ सफेद करैत, वन विभाग ने राजनांदगांव के जंगल में छोड़ा

ल्यूसिज्म के कारण सफेद था सांप, दक्षिण एशिया में बहुत कम मिलते हैं ऐसे मामले

भिलाई। दुर्ग जिले के चरोदा क्षेत्र के पंचशील नगर में एक घर से दुर्लभ श्वेतवर्णी करैत सांप मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम और सर्प विशेषज्ञों ने तत्परता दिखाते हुए उसे रेस्क्यू कर राजनांदगांव वन मंडल के घने जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया।

घर में निकला सफेद सांप : 21 जुलाई को पंचशील नगर के एक घर में सफेद रंग का सांप होने की सूचना वन विभाग को मिली। सूचना मिलते ही दुर्ग वन मंडल की टीम और सर्प रेस्क्यूअर विजय शर्मा मौके पर पहुंचे। सावधानीपूर्वक रेस्क्यू के बाद शुरुआती जांच में यह अत्यंत दुर्लभ श्वेतवर्णी करैत होने का अनुमान लगा। सर्प विशेषज्ञों ने जांच के बाद इसकी पुष्टि की। इसके बाद दुर्ग वनमंडलाधिकारी दीपेश कपिल के निर्देश पर 23 जुलाई को आर.ए. प्रमोद यादव, सर्प मित्र विजय शर्मा और सर्प विशेषज्ञ अविनाश मौर्या की टीम ने इस दुर्लभ सर्प को राजनांदगांव वनमंडल के आर.एफ. 549 क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावास में सुरक्षित छोड़ दिया।

स्वामी विवेकानंद तकनीकी विवि में NHRC के स्पेशल मॉनिटर प्रो. कन्हैया त्रिपाठी का दौरा

विद्यार्थियों के अधिकार, समावेशी शिक्षा और सुरक्षित परिसर पर दिया जोर, मानवाधिकार प्रकोष्ठ को सक्रिय बनाने के सुझाव

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के स्पेशल मॉनिटर एवं ऑब्जर्वर प्रो. कन्हैया त्रिपाठी ने बुधवार को छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय CSVTU, भिलाई का भ्रमण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के अधिकारों, सुरक्षा, कल्याण और समावेशी शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान कुलपति डॉ. अरुण अरोरा, कुलसचिव डॉ. अमित सिंह राजपूत, विभागाध्यक्षों और विभिन्न प्रकोष्ठों के समन्वयकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

"शिक्षा का उद्देश्य जिम्मेदार नागरिक बनाना"

बैठक को संबोधित करते हुए प्रो. त्रिपाठी ने कहा कि किसी विश्वविद्यालय की पहचान केवल शैक्षणिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण से होती है। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव-मुक्त शिक्षण वातावरण देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि जिम्मेदार, संवेदनशील और नैतिक नागरिक तैयार करना भी है।

इन बिंदुओं पर दिए सुझाव

प्रो. त्रिपाठी ने छात्रावासों में बेहतर सुविधाएं, शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने, मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी अधोसंरचना और विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। कहा कि शिक्षक सिर्फ विषय विशेषज्ञ नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के मार्गदर्शक होते हैं।

मानवाधिकार प्रकोष्ठ को और सक्रिय बनाने, सभी विभागों और संबद्ध महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने, वार्षिक संगोष्ठी, कार्यशाला और सेमिनार आयोजित करने के सुझाव भी दिए। साथ ही मानवाधिकार विषयक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, साइबर सुरक्षा, लैंगिक समानता, स्टार्टअप और नवाचार महोत्सव जैसे प्रस्ताव भी रखे।

विश्वविद्यालय ने दिए आश्वासन

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस अवसर पर एंटी-रैगिंग, लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। प्रो. त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें और प्रभावी बनाने के सुझाव दिए।

कुलपति डॉ. अरुण अरोरा ने कहा कि ठल्फ्ठ की सभी अनुशंसाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि परिसर में सुरक्षित और समावेशी शैक्षणिक माहौल और मजबूत हो सके। कार्यक्रम में सभी विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित थे।

खास खबर

बीएसपी ने गोढ़ी और खोपली में लगाया नि:शुल्क चिकित्सा शिविर, 90 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, नि:शुल्क दवाइयां भी वितरित

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने निगमित सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से दुर्ग जिले के दो गांवों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए। जिला चिकित्सालय दुर्ग के सहयोग से आयोजित इन शिविरों में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और दवाइयां निःशुल्क दी गईं।

गोढ़ी में 40 लोगों की जांच : 20 जुलाई 2026 को धमधा विकासखंड के ग्राम गोढ़ी में आयोजित शिविर में जिला चिकित्सालय की टीम ने सेवाएं दीं। चिकित्सा अधिकारी डॉ. गायत्री श्याम, फार्मासिस्ट जान्हवी, नर्सिंग स्टाफ तृप्ति कुमारी, पंजीयन सहयोगी राकेश कुमार और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी गुलेश्वरी साहू मौजूद रहे। शिविर में कुल 40 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें 12 पुरुष और 28 महिलाएं शामिल थीं। सभी को आवश्यक परामर्श के साथ निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं।

खोपली में 50 ग्रामीण लाभान्वित : इसी क्रम में 21 जुलाई को निकुम विकासखंड के ग्राम खोपली में दूसरा शिविर लगा। यहां डॉ. गायत्री श्याम, फार्मासिस्ट मनीष देशमुख, नर्सिंग स्टाफ रेणुका वर्मा और पंजीयन सहयोगी विवेक ध्रुव ने अपनी सेवाएं दीं। इस शिविर में 50 ग्रामीणों, जिनमें 28 पुरुष और 22 महिलाएं थीं, का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां और चिकित्सकीय सलाह दी गई। भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए इस तरह के शिविर लगातार आयोजित किए जाएंगे। शिविरों के सफल संचालन में जिला चिकित्सालय दुर्ग का सक्रिय सहयोग रहा।

नीट से लेकर अतिथि शिक्षक तक भाजपा कर रही शिक्षा से खिलवाड़ : राहुल शर्मा

दुर्ग। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के महामंत्री राहुल शर्मा ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर अतिथि शिक्षकों और शिक्षा के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों की भाजपा सरकारों को "शिक्षक एवं शिक्षा विरोधी" बताया। श्री शर्मा ने कहा कि नियमितीकरण और सिविलियन की अपनी जायज मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक संघ पिछले 23 दिन से हड़ताल पर बैठे थे। किंतु छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार और उनके नुमाइंदों ने उनकी सुध तक नहीं ली। भाजपा के घोषणा पत्र में वादा था कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी की जाएगी। सत्ता में आने के बाद भाजपा अपने वादों को भूल गई। यह भाजपा की पुरानी आदत है।

शांतिपूर्ण हड़ताल पर बैठे शिक्षकों पर दमनकारी नीति अपनाई गई। पुलिस प्रशासन द्वारा उनके टेंट उखाड़ दिए गए और उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी गई, जो अत्यंत निंदनीय है। सरकार को चाहिए था कि शिक्षकों से बात करे, स्थाई नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित करे। तत्काल वार्ता कर नियमितीकरण व मानदेय की मांगों का समाधान किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि "शिक्षा के मंदिर को बचाने वाले गुरुजनों पर तानाशाही और अत्याचार की जितनी भी निंदा की जाए कम है।"

उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को भी घेरा। कहा कि ठएएळ परीक्षा लीक होने के कारण लगभग 20 लाख छात्रों को अपनी पढ़ाई से हाथ धोना पड़ा। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज छात्र आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र की बेरहम सरकार ने छात्र-छात्राओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। इस घटना में एक छात्र की जान भी चली गई। नैतिकता के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन सत्ता लोलुप भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया। राहुल शर्मा ने कहा कि इससे साबित हो गया है कि केंद्र और राज्य दोनों की भाजपा सरकार शिक्षा एवं शिक्षक विरोधी हैं। इन्हें जल्द उखाड़ फेंकना जरूरी है, तभी हमारा देश शिक्षित होगा और आगे बढ़ेगा।

भिलाई को स्वच्छ और सुंदर बनाने समय सीमा में पूरे होंगे काम, आयुक्त सुरूचि सिंह ने की समीक्षा

ई-ऑफिस से लेकर सड़क-लाइट तक दिए निर्देश, जल संरक्षण व पीएम आवास पर भी दिया जोर

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह ने गुरुवार को निगम के विकास, निर्माण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा की। निगम मुख्य कार्यालय में हुई बैठक में सभी जोन कार्यालयों के अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने सभी लंबित कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने और नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

ई-ऑफिस और शिकायत निवारण पर जोर

आयुक्त ने निगम की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को शत प्रतिशत लागू करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी नस्तियां डिजिटल सिग्नेचर के साथ ई-ऑफिस के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएं, ताकि फाइलों के निराकरण में देरी न हो।

सभी जोन आयुक्तों को अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिदिन भ्रमण कर जमीनी समस्याओं की जानकारी लेने और मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने और लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेने को कहा गया।

सड़क, स्ट्रीट लाइट और आवास योजना की समीक्षा

बैठक में लोक निर्माण विभाग के साथ नंदिनी रोड से अवंति बाई चौक तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण पर चर्चा हुई। आयुक्त ने मुख्य मार्गों के गड्ढों को तत्काल भरने के निर्देश दिए ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने मकानविहीन पात्र परिवारों को जल्द लाभ दिलाने के लिए निर्माण कार्य समय पर पूर्ण कराने को कहा। शहर की प्रकाश व्यवस्था को लेकर प्रमुख मार्गों की बंद स्ट्रीट लाइटों का तुरंत संधारण, एलईडी सप्लाई-रिपेयरिंग और प्रमुख चौक-चौराहों पर हाईमास्ट लाइट लगाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि इससे रात में शहर अंधेरे से मुक्त होगा और नागरिक सुरक्षित आवागमन कर सकेंगे।

जल संरक्षण और अन्य निर्देश

जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए आयुक्त ने शहर में अधिक से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने और नागरिकों-व्यापारियों को इसके लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्षाजल का संरक्षण भविष्य की जरूरत है। इसके अलावा डॉग हाउस और एमआरएफ प्लांट के कार्य समय पर पूर्ण करने, अनुष्ठा रेसिडेंसी में सड़क-नाली निर्माण के लिए आवास शुल्क का उचित उपयोग, पट्टा सर्वे कार्य समय-सीमा में पूरा करने, बोरवेल के पानी की गुणवत्ता जांच और उद्यानों की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल निर्माण के निर्देश भी दिए गए। आयुक्त ने पेंशन भुगतान से जुड़े कार्यों का भी पोर्टल के माध्यम से समय पर निराकरण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि हितग्राहियों को परेशानी न हो। बैठक में अपर आयुक्त राजेंद्र दोहरे, मुख्य अभियंता अजीत कुमार तिग्गा, अधीक्षण अभियंता वेशराम सिन्हा सहित निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

"मंत्री बनकर भी नहीं भूली माटी" : गजेन्द्र यादव ने खेत में चलाया ट्रैक्टर

अहिवारा के माटरा गांव में किसानों संग की धान रोपाई की शुरुआत, कहा - "खेती-किसानी हमारे जीवन का आधार है"

नई दृष्टिबिंदु / नंदिनी अहिवारा

प्रदेश में मानसून की अच्छी बारिश के बाद खेती-किसानी के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी बीच दुर्ग शहर विधायक और प्रदेश के शिक्षा, ग्रामोद्योग तथा विधि-विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव शुक्रवार को अपने गृहग्राम अहिवारा के पास माटरा गांव के खेत पहुंचे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मंत्री बनने के बाद भी मंत्री यादव को अपनी माटी और संस्कृति से गहरा जुड़ाव नजर आया।

मंत्री श्री यादव ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर लगभग 2 एकड़ खेत की मताई की और उसे रोपाई के लिए तैयार किया। खेत का निरीक्षण कर उन्होंने खाद की उपलब्धता और तैयारियों की जानकारी ली। किसानों को समय पर निंदाई-गुड़ाई करने की सलाह भी दी। इसके बाद विधिवत रूप से खेत में धान रोपाई का काम शुरू कराया गया।

खेत में किसानों से चर्चा करते हुए केबिनेट मंत्री ने कहा कि व्यक्ति चाहे किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसे अपनी माटी, संस्कृति और मूल कार्य

को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं किसान परिवार से हूं। खेती-किसानी हमारे जीवन का आधार है। समय मिलने पर आज भी खेत में जाकर काम करता हूं।"

मंत्री बनने के बाद भी श्री गजेन्द्र यादव अपनी खेती की देखरेख स्वयं करते हैं और हर साल खेती के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उनका मानना है कि किसानों की मेहनत और कृषि के महत्व को समझने के लिए खेत से जुड़ाव बनाए रखना जरूरी है। किसान परिवार से होने के कारण वे किसानों की समस्याओं और जरूरतों को बेहतर तरीके से समझते हैं। खेत में उनकी सहभागिता छत्तीसगढ़ की माटी, संस्कृति और कृषि परंपरा के प्रति उनके आत्मीय लगाव को दर्शाती है। मंत्री की इस पहल से क्षेत्र के किसानों में उत्साह का माहौल है।

छत्तीसगढ़ स्टेट सब-जूनियर फीडे रेटेड चेस चैंपियनशिप का राकेश पाण्डेय ने किया शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन में जिला शतरंज संघ दुर्ग द्वारा इस्पात नगरी भिलाई के सेक्टर 6 जैन भवन में आयोजित 'छत्तीसगढ़ स्टेट सब-जूनियर फीडे रेटेड चेस चैंपियनशिप 2026' का भव्य शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश शतरंज संघ के कोषाध्यक्ष प्रदीप दास ने किया। इस अवसर पर जिला शतरंज संघ दुर्ग के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत, इंटरनेशनल आर्बिटर रॉकी देवांगन, मुख्य निर्णायक इंटरनेशनल आर्बिटर अनीस अंसारी, सहायक निर्णायक इंटरनेशनल आर्बिटर शुभम बसोंने, फिडे आर्बिटर अनिल शर्मा विशेष रूप से मंचासिन थे।

जिला शतरंज संघ दुर्ग के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत सचिव तुलसी सोनी ने स्पर्धा संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के 19 जिलों के 142 शतरंज प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। स्पर्धा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 4 बालक एवं 4 बालिकाओं का चयन राष्ट्रीय सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि राकेश पाण्डेय ने शतरंज की चाल चलकर चैम्पियनशिप का शुभारंभ कर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल में हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खिलाड़ी को हार से हताश होने के बजाय अपनी कमियों से सीखना चाहिए, क्योंकि वही सीख भविष्य में बड़ी जीत का आधार बनती है।

उन्होंने इंडियन आइडल के फाइनलिस्ट तनिष्क शुक्ला की प्रेरक कहानी साझा करते हुए बताया कि जब तनिष्क मानसिक अवसाद (डिप्रेशन) के दौर से गुजर रहे थे, तब चेस ने ही उन्हें इस तनाव से मुक्ति दिलाई। शतरंज ने उनकी एकाग्रता लौटाई और मानसिक ऊर्जा दी, जिसके बल पर वे संगीत के राष्ट्रीय

मंच इंडियन आइडल पर शीर्ष तक पहुँचे। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदीप दास ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बाल खिलाड़ियों को उनके उज्वल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शतरंज जैसे बौद्धिक खेल से बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होता है और संघ सदैव प्रदेश की चेस प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा।

समारोह के दौरान लोरमी के प्रतिभावान खिलाड़ी अंशुल शर्मा को 10वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए मुख्य अतिथि राकेश पाण्डेय एवं मंचासीन अतिथियों द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अतिथियों ने उनकी इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि अंशुल ने साबित किया है कि सही समय प्रबंधन और एकाग्रता से खेल और पढ़ाई दोनों में ही सर्वोच्च शिखर छुआ जा सकता है।

प्रतियोगिता का संचालन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जा रहा है जिसमें देश के जाने-माने आर्बिटर्स अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इन्टरनेशनल आर्बिटरः रॉकी देवांगन, मुख्य आर्बिटरः अनीश अंसारी उप-मुख्य आर्बिटरः शुभम बसोने यह आयोजन प्रदेश के युवा शतरंज खिलाड़ियों के बौद्धिक विकास और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करने की दिशा में बेहद सफल साबित होगा। अतिथियों का स्वागत फिडे आर्बिटर सुरेश होता, ममता देवांगन, ओमप्रकाश बंदे, दिव्यांशु उपाध्याय, एवं सुरेन्द्र बल्लेवार ने पुष्प गुच्छ देकर किया। स्पर्धा 8 चक्रों में खेली जाएगी। कार्यक्रम का संचालन जिला शतरंज संघ दुर्ग के सचिव तुलसी सोनी एवं आभार प्रदर्शन संघ के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत ने किया।

भिलाई निगम क्षेत्र में विकास कार्यो को मिली गति

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देने के लिए विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों को तेज किया गया है। आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह के निर्देश पर शहर के कई क्षेत्रों में सड़क निर्माण, रोड सीमेंटीकरण और नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर है। निगम प्रशासन का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाते हुए लोगों की दैनिक जरूरतों से जुड़े कार्यो को प्राथमिकता से पूरा करना है।

किन क्षेत्रों में चल रहा काम

एसबीआई कॉलोनी: 15वें वित्त आयोग मद से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। **मार्ग चौड़ीकरण:** नगरोत्थान मद से सड़कों को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। **अनुष्ठा रेसिडेंसी:** विकास शुल्क मद से रोड और नाली निर्माण कार्य चल रहा है। **कैलाश नगर, महावीर मार्ग:** यहां सीमेंटीकरण का कार्य हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। **कुरूद, सुंदर विहार कॉलोनी:** सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। **जामुल ट्रेंचिंग ग्राउंड:** निर्माणाधीन डॉग हाउस में जल निकासी के लिए नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

निगम अधिकारियों ने बताया कि सभी कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराए जा रहे हैं। इन कार्यों के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में सुगम आवागमन के साथ बेहतर जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध होंगी। निगम प्रशासन ने कहा कि क्षेत्र की आवश्यकताओं और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही विकास कार्यो की योजना बनाई जा रही है।

डॉ अंजना के काव्य संग्रह 'अंतहीन अनदेखी सिसकियां' का पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने किया विमोचन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने समाजशास्त्री डॉ अंजना श्रीवास्तव के काव्य संग्रह 'अंतहीन अनदेखी सिसकियां' का विमोचन पुलिस कंट्रोल रूम के सभागार में किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मणिशंकर चंद्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

मुख्य अतिथि विजय अग्रवाल ने पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर के रूप में विगत 35 वर्षो से निरंतर निःस्वार्थ सेवाएं देने के लिए डॉ अंजना श्रीवास्तव की भूरि भूरि प्रशंसा की और उनके द्वारा रचित काव्य संग्रह को मानवीय संवेदनाओं का एक दस्तावेज बताया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सुखनंदन राठौर तथा मणिशंकर चंद्रा विमोचित काव्य संकलन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी।

कवित्री डॉ अंजना श्रीवास्तव ने कहा कि विगत 70 वर्षों में उन्होंने समाज में मानवीय संबंधों के

परिवर्तन को बारीकी से देखा है, समाज में उत्पन्न विसंगतियां, विद्रूपताओं और जटिलताओं को उन्होंने अपने काव्य संग्रह में कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

इस अवसर पर शिक्षाविद डॉ डी एन शर्मा, चिकित्सक डॉ अशोक कुमार, डॉ सरोज प्रकाश, डॉ स्वामी कन्नमवाल, विश्व प्रकाश, प्रीति बेहरा, महेश चतुर्वेदी, प्रदीप भट्टाचार्य, रत्ना नारमदेव, अशोक जोशी, डॉ विश्वकर्मा, उप पुलिस अधीक्षक सहित समाजसेवी व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समाजशास्त्री डॉ सुचित्रा विश्वकर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। आभार प्रदर्शन काउंसलर डॉ शशि कुमार ने किया।

एक पेड़ मां के नाम : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नि:शुल्क पौधा वितरण वैन को दिखाई हरी झंडी

अब एक कॉल पर घर पहुंचेगा नि:शुल्क पौधा, वन विभाग की अभिनव पहल से बढ़ेगी हरियाली, फलदार और छायादार पौधे होंगे उपलब्ध

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने रायगढ़ प्रवास के दौरान आज अपने निवास कार्यालय से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वनमंडल रायगढ़ द्वारा संचालित नि:शुल्क पौधा वितरण वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभिनव पहल के माध्यम से रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के नागरिक अब केवल एक फोन कॉल पर अपने घर तक नि:शुल्क पौधे प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल प्रधानमंत्री के श्एक पेड़ मां के नामश अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

घर बैठे मिलेगी पौधों की सुविधा : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि वन विभाग की यह पहल नागरिकों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने की दिशा में सराहनीय प्रयास है। अब यदि कोई व्यक्ति अपने घर, आंगन, बाड़ी, खेत, बगीचे, तालाब किनारे अथवा अन्य उपयुक्त स्थान पर पौधारोपण करना चाहता है, तो उसे केवल टोल-फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। इसके बाद वन विभाग की टीम सीधे उसके घर पहुंचकर नि:शुल्क पौधे उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से लोगों को पौधों के लिए नर्सरी या विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अधिक से अधिक लोग पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान से जुड़ सकेंगे।

एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़ने की अपील : श्री चौधरी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। श्एक पेड़ मां के नामश अभियान प्रकृति के प्रति सम्मान और मातृऋण के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे, तो आने वाले समय में रायगढ़ हरियाली की नई पहचान बन सकता है।

फलदार और छायादार पौधों की रहेगी उपलब्धता : मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत वन विभाग द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार आम, अमरूद, नींबू सहित विभिन्न फलदार पौधों के साथ-साथ छायादार एवं अन्य उपयोगी प्रजातियों के पौधे भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण पौधों की सहज उपलब्धता से पौधारोपण अभियान को नई गति मिलेगी।

हर नागरिक लगाए एक पेड़, हरामरा बने रायगढ़ : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घर, बगीचे, खेत, तालाब किनारे, पार्क अथवा अन्य उपलब्ध स्थानों पर पौधारोपण कर प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। एक पेड़ केवल हरियाली ही नहीं देता, बल्कि स्वच्छ हवा, संतुलित पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य का आधार भी बनता है। उन्होंने नागरिकों से वन विभाग की इस जनहितैषी पहल का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।

नगर निगम क्षेत्र के नागरिक टोल-फ्री नंबर 8305186853 एवं 18002332631 पर कॉल कर फलदार, छायादार और अन्य उपयोगी प्रजातियों के पौधे नि:शुल्क मंगा सकेंगे। इस अवसर पर महापौर जीवर्धन चौहान, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, डीएफओ अरविंद पीएम, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

खास खबर

राज्यपाल रमेन डेका से निजी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों ने की भेंट

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका से यहां लोकभवन में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित प्रावधानों पर राज्यपाल से विचार-विमर्श किया। श्री डेका ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार के सबंद्ध में अपने विचार साझा किए।

इस अवसर पर मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति गजराज पगारिया, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी व भिलाई दुर्ग के कुलाधिपति आईपी मिश्रा, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलाधिपति सुशील चंद्राकर, कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति डॉ. संदीप अरोड़ा, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, गरियाबंद और रायपुर के कुलपति डॉ. आनंद महलवार, अंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति अभिषेक अग्रवाल, दावड़ा विश्वविद्यालय रायपुर के सीईओ चिन्मय दावड़ा, कोलंबिया विश्वविद्यालय रायपुर के प्रो. कुलाधिपति हरजीत सिंह हूरा उपस्थित थे।

बिलासपुर संभागायुक्त ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण

मेडिकल कॉलेज भवन, छात्रावास, ऑडिटोरियम सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति का लिया जायजा

रायपुर। बिलासपुर संभागायुक्त सुनील जैन ने आज जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम कुटरा स्थित निर्माणाधीन शासकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज भवन, ऑडिटोरियम, छात्रावास, पहुंच मार्ग सहित निर्माणाधीन अधोसंरचनाओं का अवलोकन करते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उपयोग और निर्धारित तकनीकी मानकों के पालन के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त श्री जैन ने सीजीएमएससी के नोडल अधिकारियों से मेडिकल कॉलेज परियोजना की प्रगति, विभिन्न भवनों के निर्माण तथा अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने परियोजना की समय-सीमा की समीक्षा करते हुए संबंधित एजेंसी एवं अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में सभी तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में विद्यार्थियों एवं मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज परिसर में श्एक पेड़ मां के नामश अभियान के तहत पौधरोपण भी किया गया। संभागायुक्त सुनील जैन ने पीपल तथा कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आम का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कमर्चारी उपस्थित रहे।

रायगढ़ जिले के विकास को मिली नई रफ्तार, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

फोर-लेन सड़क, गोवर्धनपुर पुल, मरीन ड्राइव, ऑक्सीजोन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लिया जायजा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार रायगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शहर में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

वित्त मंत्री चौधरी ने फोर-लेन सड़क, गोवर्धनपुर पुल, मरीन ड्राइव, दूध डेयरी एवं एफसीआई ऑक्सीजोन, चांदमारी, मोदीनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तथा लोहरसिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रत्येक स्थल पर अधिकारियों से तकनीकी प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता, निर्धारित समय-सीमा तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी ली और सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

फोर-लेन सड़क से यातायात होगा अधिक सुगम

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए कोतरारोड थाना चौक से डिमरापुर, डिमरापुर से सीएमएचओ कार्यालय तिराहा तथा सर्किट हाउस मार्ग सहित विभिन्न हिस्सों में फोर-लेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसके पूरा होने से यातायात व्यवस्था अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित होगी तथा नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने बताया कि गोवर्धनपुर पुल शहर की बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं में शामिल है। इसका कार्यादेश जारी हो चुका है और शीघ्र ही निर्माण कार्य गति पकड़ेगा। पुल के निर्माण से शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा और वर्षों पुरानी आवागमन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा।

दशकों से लंबित परियोजनाओं को मिल रही प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने कहा कि रायगढ़ की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं पिछले तीन-चार दशकों से विभिन्न कारणों से लंबित थीं। राज्य सरकार इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है, ताकि नागरिकों को आधुनिक शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य रायगढ़ को आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिक सुविधाओं से समृद्ध शहर के रूप में विकसित करना है। इसके लिए मौसम की परवाह किए बिना विकास कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है, जिससे जनता को जल्द से जल्द इन परियोजनाओं का लाभ मिल सके।

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं

श्री चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्रीलाल साहू, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में ई-मालखाना 2.0 की हुई शुरुआत

जब्त संपत्तियों का अब डिजिटल प्रबंधन, हर सामान पर लगेगा बारकोड, थाना देवेंद्र नगर में हुआ शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने जब्त संपत्तियों के प्रबंधन को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मध्य जोन के थाना देवेंद्र नगर में बुधवार को "ई-मालखाना 2.0" का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले ने किया।

क्या है ई-मालखाना 2.0: इस नई व्यवस्था के तहत अब थानों में रखी गई जब्त संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन ऐप के माध्यम से रखा जाएगा। प्रत्येक जब्त सामान पर एक यूनिक बारकोड चिपकाया जाएगा। बारकोड को स्कैन करते ही उस संपत्ति से जुड़ी सारी जानकारी तुरंत स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे संपत्ति की खोज, सत्यापन, रिकॉर्ड संधारण और न्यायालय में पेशी के दौरान जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद : शुभारंभ के मौके पर पुलिस उपायुक्त (मध्य) तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विवेक शुक्ला, सहायक पुलिस आयुक्त रमाकांत साहू और थाना देवेंद्र नगर प्रभारी दीपेश सैनी सहित समस्त पुलिस स्टाफ उपस्थित था।

पहले भी 3 थानों में हो चुका सफल प्रयोग: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले कोतवाली, गंज और मोदहापारा थाना में भी ई-मालखाना व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। अब इसे चरणबद्ध तरीके से कमिश्नरेट के सभी थाना क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

तकनीक से बढ़ेगी पारदर्शिता: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले ने कहा कि ई-मालखाना 2.0 का मुख्य उद्देश्य जब्त संपत्तियों के रख-रखाव में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। तकनीक आधारित पुलिसिंग से न सिर्फ पुलिस का काम आसान होगा, बल्कि आम जनता का भरोसा भी बढ़ेगा।

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सभी थानों को इस आधुनिक व्यवस्था से जोड़ा जाए, ताकि जब्त माल के गायब होने या रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायतें पूरी तरह खत्म हो सकें।

उप मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव का किया शुभारंभ, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील

बैगाकापा से हरित अभियान की शुरुआत, वृक्ष मित्र वाहन को दिखाई हरी झंडी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जनआंदोलन बनाने एक पेड़ मां के नाम अभियान 3.0 का शुभारंभ लोरमी विकासखण्ड के ग्राम बैगाकापा में किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल्पवृक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता फैलाने वृक्ष मित्र वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन गाँवों-शहरों में जाकर नीम, मुनगा, बिही, जामुन आदि के पौधे वितरित कर नागरिकों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करेगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि जलवायु परिवर्तन आज वैश्विक चुनौती है और इससे निपटने के लिए वृक्षारोपण के साथ वर्षा जल का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति के संतुलन के लिए पेड़, पानी और पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौती का उल्लेख करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्रेरित किया, ताकि ग्रीष्मकाल में जल संकट से बचा जा सके।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, ग्रामीणों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कलेक्टर कुन्दन कुमार, वनमंडलाधिकारी अभिनव कुमार, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय और जिला पंचायत के सीईओ गोकुल रावटे के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामीणजन और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

तुपकी' की सलामी और भक्ति भाव के बीच संपन्न हुआ बस्तर का प्रसिद्ध गोंचा पर्व

भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र की बाहुड़ा रथयात्रा के साथ मंदिर वापसी, वन मंत्री केदार कश्यप सहित जनप्रतिनिधियों ने की पूजा-अर्चना, क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रसिद्ध गोंचा पर्व छत्तीसगढ़ के बस्तर (जगदलपुर) अंचल में मनाया जाने वाला एक अनूठा और ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक उत्सव है। यह भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा से जुड़ा है और इसकी मुख्य विशेषता तुपकी, गोंचा फल तथा 600 साल पुरानी परंपरा है। बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक प्रसिद्ध गोंचा पर्व आज भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा रथयात्रा के साथ श्रद्धा और उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र जनकपुरी (गुंडिचा मंदिर) से रथ पर सवार होकर अपने मुख्य मंदिर लौटे।

बाहुड़ा गोंचा के अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने रथयात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना की। उन्होंने क्षेत्र की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।

'तुपकी' की सलामी बनी आकर्षण का केंद्र

रथयात्रा के दौरान बस्तर की अनूठी और सदियों पुरानी परंपरा 'तुपकी' की सलामी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। बांस से बनाई गई विशेष नाल 'तुपकी' में पेंग (मलकांगनी) के बीज भरकर श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ को पारंपरिक सलामी दी।

तुपकी से निकलने वाली मधुर आवाज और श्रद्धालुओं के उत्साह से पूरा जगदलपुर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और रथयात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को मिल रहा संरक्षण

गोंचा पर्व बस्तर की प्राचीन लोक परंपराओं, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और धार्मिक उत्सवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में बस्तर की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा रथयात्रा के साथ ही बस्तर के इस अनूठे और ऐतिहासिक लोक पर्व गोंचा का विधिवत समापन हुआ।

संपादकीय

पीएम ने तो कह दिया कड़ी सजा मिलनी चाहिए

देश में नीट पेपर लीक को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। तमाम नेताओं,परिवारों, छात्रों, राजनीतिक दलों के बयान इस मामले में आ चुके हैं। सब यही तो चाहते हैं कि इसके लिए जो दोषी लोग हैं, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई इस तरह का अपराध करते हुए डरे। सब यही तो चाहते हैं कि देश नीट परीक्षा ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, जिसमें देश भर से लाखों युवा शामिल होते हैं,उसके पेपर लीक नहीं होने चाहिए। पीएम मोदी से भी इस मामले में कुछ कहने की उम्मीद की जा रही थी। पीएम ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में दो टूक कह दिया है कि यह नीट पेपर लीक घोर पाप है। इस घोर पाप में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं ताकि कोई भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न कर सके।भविष्य मे ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि यह देश हित का मामला है।

पीएम मोदी ने सच कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में तुरंत कारर्वाई की गई है। 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दोबारा परीक्षा कराकर परिणाम घोषित कर दिया गया है। जहां तो दोषी लोगों को सजा दिलाने की बात है तो यह तो सरकार का काम नहीं है। यह तो अदालत का काम है।नीट पेपर लीक मामले में दोषी लोगों को कैसे कड़ी सजा हो सकती है, देश के वरिष्ठ वकीलों को इसके लिए सामने आना चाहिए। जहां तक परीक्षा के लिए और बेहतर व्यवस्था बनाने का सवाल है तो यह देश की समस्या है इसका समाधान सड़क पर तो नहीं हो सकता,संसद में ही हो सकता है इसलिए इस पर संसद में बहस होनी चाहिए और सभी दलों को इसमें चर्चा कर सुझाव देना चाहिए कि नीट परीक्षा की ऐसी व्यवस्था कैसे बन सकती है कि कोई पेपर लीक न कर सके। राज्यों में जब पेपर लीक हुआ करते थे तो कांग्रेस शासित राज्यों के नेता यह कहते थे कि यह राज्य की समस्या नहीं है यह को केंद्र की समस्या है।देश की समस्या है तो इसका समाधान सभी राष्ट्रीय दलों के सरकार के साथ मिलकर ढूंढना होगा।

सरकार तो चाहती है कि नीट पेपर लीक मामले में संसद में सार्थक बहस हो ताकि इस समस्या का कोई समाधान तलाशा जा सके। विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित पेपर लीक मामले में आंदोलन कर रहे संगठन व राजनीतिक दल यही नहीं चाहते हैं वह संसद में चर्चा के लिए शर्त जोड़ देते हैं, आए दिन नई नई शर्त जोड़ देते हैं कि सरकार ऐसा करेगी तब ही हम संसद में नीट पेपर लीक मामले में चर्चा करेंगे। सब इस मामले होड़ कर रहे हैं कि इस मामले को कौन कितने जोर शोर से उठा सकता है। एक संगठन जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है, वांगचुक अस्पताल में अनशन कर रहे हैं। जंतर मंतर वालों की पहले एक ही मांग थी अब वह एक से ज्यादा हो गई है। वांगचुक की मांगें भी बदलती रही है,राहुल गांधी की मागें भी बदलती रही है। जब उन्होंने पीएम आवास के बाहर धनना दिया तो उनकी मांग थी कि नीट पेपर लीक मामले मे संसद मे चर्चा होनी चाहिए।सरकार इस पर राजी हो गई तो उनकी मांग बढ़ गई उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा,पीएम छात्रों से माफी मांगेंगे तो ही संसद में वह चर्चा करेंगे।

राहुल गांधी सहित अलग संगठनों की मांगें ऐसी हैं कि सरकार उनको पूरा नहीं कर सकती। क्योंकि सभी मांगें जायज नहीं है क्योंकि इससे युवाओं का कोई हित नहीं होता है, परीक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी,यह तो राजनीति है,यह तो सरकार को झुकाने का प्रयास है और देश के युवाओं को संदेश देने का प्रयास है कि देखो जो जंतर मंतर में बैठे हैं वह सरकार को नहीं झुका सकते, सरकार को हम झुका सकते हैं, इसलिए युवाओं को हमपर भरोसा करना चाहिए। राहुल गांधी तो कहते रहे हैं यह कमजोर सरकार है,पीएम मोदी कमजोर पीएम है, वह चीन व अमरीका के सामने सरेंडर कर देते है।ऐसे भी मोदी सरकार राहुल गांधी के न मानने योग्य मांगों को मानकर राहुल गांधी की बातों को सच तो साबित नहीं कर सकती। राहुल गांधी भी जानते हैं कि वह जो मांग कर रहे हैं,वह मोदी सरकार मानने से रही। मोदी सरकार मानेगी नहीं और संसद में नीट पेपर लीक पर बहस नहीं होगी और इस मुद्दे पर देश में संसद के भीतर व बाहर बवाल होता रहेगा।

राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उनकी जिम्मेदारी विपक्ष को एकजुट करना और मजबूत करना है लेकिन नीट पेपर लीक मामले में वह कांग्रेस के राजनीतिक हित के लिए विपक्ष को भरोसे में लेकर काम नहीं कर रहे हैं। इससे उन पर आम आदमी पार्टी को आरोप लगाने का मौका मिल रहा है कि राहुल गांधी व कांग्रेस युवाओं का आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। नाराज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में कह दिया कि कांग्रेस व सरकार के बीच समझौता हो गया है क्योंकि राहुल गांधी व कांग्रेस नेताओं ने पीएम आवास के पास धरना दिया तो इस बात की जानकारी अखिलेश को पहले नहीं दी गई, बाद में दी गई और वह देर से पहुंच थे धरनास्थल पर। अखिलेश यादव का मानना है कि नीट आंदोलन का श्रेय कांग्रेस अकेले लेना चाहती है, अकेले राहुल गांधी को देना चाहती है। वह कांग्रेस व सपा के बीच आपसी तालमेल ठीक नहीं होने से नाराज हैं। संसद में उनको बोलने का मौका जल्दी नहीं दिए जाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। यह कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया है,इससे पहले कांग्रेस ने तमिलनाडु मे अपने राजनीतिक फायदे के लिए द्रमुक को धोखा दिया है। अब आप व सपा को दिया है, यह बात विपक्ष को पसंद नहीं आ रही है और इसका नुकसान विपक्ष की एकजुटता को हो रहा है।

डिजिटल चुनौती के बीच कैसे जिएं अखबार

पठनीयता के गहरे संकट से जूझते समाचार पत्र क्या करें?

संजय उवाच

प्रो. संजय द्विवेदी

हां, सामने मीडिया की पढ़ाई करने की चाह रखने वाले विद्यार्थी ही थे, उम्मीद की जानी चाहिए कि वे कोई अखबार, मैगजीन या किताबें पढ़कर आए होंगे। लगभग 110 विद्यार्थियों से बात करते हुए यह अहसास हुआ कि अखबार अब उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखता। वे जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, आनलाइन ही कर रहे हैं। ऐसे में प्रिंट मीडिया के सामने बहुत गहरे संकट हैं। क्योंकि इस डिजिटल समय में उनके ई-पेपर ही पलटे जा रहे हैं। क्या अब हाथ में अखबार लेकर पढ़ने वाले दुर्लभ हो जाएंगें?

बदल गए हैं पढ़ने के तरीके

डिजिटल मीडिया और स्माटफोन ने पढ़ने के तरीके को बदलकर रख दिया है। पोर्टल्स, सोशल मीडिया और न्यूज एप्स के कारण पाठकों को पल-पल की खबरें मुफ्त में उनके मोबाइल पर मिल रही हैं। जिससे 24 घंटे में एक बार आनेवाला अखबार क्या मुकाबला करेगे। रीयल टाइम अपडेट एक ऐसी घटना है जिसने सारा कुछ बदलकर रख दिया है। ऐसे में अखबारों को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए नए रास्ते तलाशने की जरूरत है। नई पीढ़ी लंबी सामग्री पढ़ने के बजाए अब वीडियो, शार्ट्स, पाडकास्ड और विजुअल इंफ्रोग्राफिक्स के जरिए चीजों को देखना,सुनना और समझना सीख गई है। प्रिंट मीडिया के प्रति उसका आकर्षण खत्म सा है।

आर्थिक संकट से भी हैं हलाकान

इस परिघटना ने प्रिंट मीडिया से कमाई के मौके भी छीनने शुरु कर दिए हैं। हम जानते हैं अखबार मूलतः विज्ञापनों (स्पेस सेलिंग) पर निर्भर हैं। अब जबकि कंपनियां अपना बड़ा बजट डिजिटल प्लेटफार्म जैसे गूगल,मेटा और यू-ट्यूब पर खर्च कर रही हैं, जहां वे अपने लक्षित समूह (टारगेट आडियंस) तक आसानी से पहुंच रही हैं। इसकी लागत भी कम पड़ रही है। एल्गोरिद्म ने बाजार और ग्राहक की पहुंच को बहुत आसान बना दिया है। कागज, स्याही और छपाई की बढ़ती कीमतों से अखबार पहले ही हलाकान थे, बिजली और प्रिंटिंग मशीनों का रख-रखाव उनकी अलग चिंताओं को बढ़ाता रहा है। इन स्थितियों में अखबार की न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि उसे लोगों तक पहुंचाना सरल नहीं रह गया है। अखबारों को सुबह छापना और लोगों के घरों तक पहुंचाना हमेशा ही कठिन काम था। भारत जैसे बाजार में जहां लोग पढ़ने के लिए खर्च को तैयार नहीं है, यह संकट और जटिल हो जाता है। आज भी हिंदुस्तान के बाजार में अखबार 3 से 7 रूपए के बीच ही बेचे जा रहे हैं। जो उसकी वास्तविक लागत से बहुत कम होता है। विज्ञापनों में आती कमी के बीच इसे छापना असंभव होता जाएगा। हम ध्यान से देखें तो हाकरों की नई पीढ़ी की रूचि अखबार बांटने में रूचि कम रख रही है। दूध या अन्य व्यवसाय के साथ अखबार वितरण भी किया जा रहा है। स्टाल कम हो रहे हैं जहां पत्र-पत्रिकाएं मिला करती थीं। स्टेशनों से लेकर नगरों, कस्बों तक अखबारों और पत्रिकाओं के स्टाल समाप्त हो रहे हैं या उनपर खाद्य सामग्री बिक रही है।

भरोसे का संकट बड़ी चुनौती

टीवी और डिजिटल मीडिया से होड़ कर रहे प्रिंट मीडिया ने भी गहरी रिपीटिंग और विश्लेषणात्मक सामग्री के बजाए हल्की-फुल्की प्रस्तुति से खुद को अप्रासंगिक बना लिया है। बहुत कम अखबार हैं जो सामग्री की गुणवत्ता और विचारों पर ध्यान क्रेंद्रित कर रहे हैं। ऐसे में जब आनलाइन उपलब्ध सामग्री जैसे ही विषयवस्तु अखबारों में होगी तो निश्चित ही पाठक दूर जाएंगें। कागज के निर्माण में पेड़ों की कटाई और जल की खपत जैसे मुद्दे उठाकर भी अखबारों से दूर करने की एक नैतिक और व्यवहारिक चिंताएं खड़ी करने के प्रयास भी हो रहे हैं। ऐसे में राजस्व में गिरावट के कारण जहां मझोले और छोटे अखबारों के सामने अस्तित्व का संकट है तो बड़े अखबार भी संपादकीय बजट में कटौती, पत्रकारों की छंटनी जैसे काम कर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में अखबारों की अधिकाधिक निर्भरता कारपोरेट और सरकारी विज्ञापनों पर बहुत बढ़ गई है। संकट का असली सिरा यहीं है। भरोसे,विश्वसनीयता का संकट इन्हीं सब कारणों से बढ़ रहा है। निष्पक्ष पत्रकारिता बहुत चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।

आखिर रास्ता क्या है

जाहिर है संकटों से घिरे प्रिंट मीडिया के सामने विकल्प सीमित हैं। अब केवल संकटों की बात, समस्याओं का बातें करने से आगे समाधान परक पत्रकारिता की आवश्यक्ता है। जिसमें अखबार संकटों के साथ उनके संभावित समाधानों, सफल माडल्स और सकारात्मक प्रयासों की बात भी करें। व्याख्या, विश्लेषण और खोजी पत्रकारिता पर फोकस करके उन्हें खबर क्यों घटी और इसके मायने क्या हैं बताने होंगे।

अखबार अब सूचना के वाहक नहीं उनके विश्लेषण और व्याख्याओं के वाहक बनें। डेटा, शोध और गहन मैदानी कवरेज ही वह रास्ता है जिससे प्रिंट स्वयं को प्रासंगिक बनाए रख सकता है। फैक्ट चेकिंग की अनिवार्यता के साथ हमें गलत खबरों का पर्दाफाश भी करना होगा। सबसे पहले खबर देने के बजाए सबसे सटीक खबर देने के सिद्धांत पर लौटना होगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर वित्तीय माडल पर काम करते हुए पाठक द्वारा पोषित मीडिया खड़ा करना होगा। पत्रकारों को तकनीक से डरने के बजाय उसका इस्तेमाल अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। डेटा एनालिसिस, ट्रांसक्रिप्शन, अनुवाद और रूटीन री-लेखन में एआई (अक) का इस्तेमाल करें ताकि पत्रकारों का समय फील्ड वर्क, मानवीय संवेदनाओं की कहानियों और खोजी रिपोर्टिंग में लग सके। पत्रकारिता तब तक निष्पक्ष नहीं हो सकती जब तक पत्रकार स्वयं सुरक्षित और आर्थिक रूप से निश्चिंत न हों।

मीडिया साक्षरता भी है जरुरी

मीडिया संस्थानों और समाज को मिलकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले संवाददाताओं के लिए सुरक्षा कवर, बीमा और सम्मानजनक मानदेय सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाना होगा। पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को आम जनता के बीच 'मीडिया साक्षरता' की समझ बहुत जरूरी है। जब पाठक यह समझना सीख जाएंगे कि कौन-सी खबर प्रायोजित है, कौन-सा एजेंडा है और कौन-सी वास्तविक पत्रकारिता, तो वे खुद-ब-खुद घटिया और सनसनीखेज कंटेंट को नकारना शुरू कर देंगे। भरोसा वह शब्द है जो आसानी से अर्जित नहीं होता, अखबारों की स्वीकायर्ता में विश्वसनीयता और प्रामणिकता का सर्वाधिक योगदान होगा। उम्मीद की जानी कि नई डिजिटल चुनौतियों के बीच भी कुछ लोग उस भरोसे को कायम रखेंगें, जो भारतीय पत्रकारिता ने अपनी लंबी यात्रा से अर्जित किया है।

(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं।)

कर-संस्कृति : विकसित भारत का अदृश्य संविधान

कृति आरके जैन

राष्ट्र की शक्ति केवल मतगणना से नहीं, करगणना से भी मापी जाती है। मतपत्र नागरिक की राजनीतिक चेतना का प्रतीक है, तो आयकर रिटर्न उसकी आर्थिक निष्ठा का। विडंबना यह है कि मतदान पर व्यापक विमर्श होता है, पर कर-अनुशासन पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखती। जबकि किसी भी आधुनिक राष्ट्र की स्थिरता का वास्तविक आधार उसकी कर-संस्कृति होती है। 24 जुलाई का आयकर दिवस इसी मौन सत्य का स्मरण कराता है कि राष्ट्र का भविष्य केवल बजट नहीं, बल्कि करोड़ों ईमानदार करदाताओं के निष्ठापूर्ण योगदान से आकार लेता है। विकसित भारत का आधार केवल नीतियाँ नहीं, बल्कि उत्तरदायी कर-संस्कृति है। इसलिए आयकर दिवस किसी विभागीय औपचारिकता का नहीं, आर्थिक नागरिकता के सम्मान का अवसर है।

इतिहास गवाह है कि समृद्ध राष्ट्रों की नींव केवल संसाधनों पर नहीं, सुदृढ़ कर-संस्कृति पर टिकी होती है। भारत में आधुनिक आयकर व्यवस्था का औपचारिक आरंभ 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत आयकर अधिनियम से हुआ, किंतु स्वतंत्र भारत ने इसे केवल राजस्व-संग्रह नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास का माध्यम बनाया। 1961 के आयकर अधिनियम के बाद सरलीकरण की दिशा में नया आयकर कानून भी प्रस्तावित/लागू होने की प्रक्रिया में है, प्रत्यक्ष कर प्रशासन में सुधार, कंप्यूटरीकरण, केंद्रीकृत प्रसंस्करण और डिजिटल कर प्रणाली उसी दृष्टि के क्रमिक विस्तार हैं। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है और वैश्विक संस्थाएँ उसे आने वाले दशक का विकास-प्रेरक मान रही हैं। इस उपलब्धि के मूल में करोड़ों ईमानदार करदाताओं से निर्मित वही राजस्व है, जिसने विकास की गति को निरंतर बनाए रखा।

हर सार्वजनिक उपलब्धि के पीछे एक मौन निवेश छिपा होता है—करदाता का। राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, नई शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित संस्थानों, रक्षा आधुनिकीकरण, डिजिटल अवसंरचना, अंतरिक्ष अनुसंधान, जल संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वास्तविक नींव ईमानदारी से अदा किए गए कर पर टिकी है। नागरिक अपनी आय का एक अंश राष्ट्र को देकर केवल राजस्व नहीं देता, बल्कि समान अवसरों वाले भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। इसलिए विकसित देशों में कर भुगतान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। भारत भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा है, जहाँ करदाता राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का सह-शिल्पी माना जाता है।

कर प्रशासन का नया चेहरा कानूनों से कम, तकनीक से अधिक गढ़ा गया है। कभी आयकर कार्यालयों के चक्कर, कागजी फाइलें और लंबी प्रतीक्षाएँ करदाताओं की विवशता थीं; आज फेसलेस असेसमेंट, प्री-फिल्ड आयकर रिटर्न, ऑनलाइन सत्यापन, डिजिटल भुगतान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जोखिम विश्लेषण ने प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित और विश्वसनीय बना दिया है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में निरंतर वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि सरल व्यवस्था स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देती है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों ने भी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत की प्रगति को उल्लेखनीय माना है। तकनीक का उद्देश्य केवल निगरानी नहीं, बल्कि करदाता और शासन के बीच भरोसे का स्थायी सेतु बनाना है। इसलिए आज करदाता व्यवस्था से डरता नहीं, उस पर भरोसा करता है।

कर भुगतान का सबसे बड़ा लाभ सरकार नहीं, स्वयं करदाता प्राप्त करता है। नियमित आयकर रिटर्न आय, व्यय, निवेश और बचत का अनुशासित लेखा विकसित करता है, जो बैंकिंग, ऋण, उद्यमिता और वित्तीय सुरक्षा की मजबूत आधारशिला बनता है। जनधन, डिजिटल भुगतान, यूपीआई और औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार ने नागरिक को अधिक वित्तीय रूप से जागरूक बनाया है। आज करदाता केवल कर अदा करने वाला नहीं, बल्कि आर्थिक अनुशासन का प्रतिनिधि है। विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती वित्तीय साक्षरता इसी परिवर्तन का संकेत है। नई पीढ़ी जब कर को दंड नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व मानेगी, तभी आर्थिक राष्ट्रवाद विचार नहीं, व्यवहार बनेगा।

कर नीति अब केवल आय का साधन नहीं, आने वाले भारत की दिशा तय करने का माध्यम भी है। स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हरित निवेश, टिकाऊ उद्योग और ऊर्जा-दक्ष तकनीकों को प्रोत्साहन इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच भारत ने नेट-जीरो उत्सर्जन सहित अनेक दीघर्कालिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ऐसे में कर व्यवस्था केवल आर्थिक गतिविधियों को नहीं, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को भी गति दे रही है। कर प्रोत्साहनों से उद्योग और नागरिक हरित विकल्प अपनाते हैं, तो उसका लाभ वर्तमान से आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचता है। इस प्रकार आयकर व्यवस्था अब राजस्व-संग्रह से आगे बढ़कर सतत विकास की प्रभावी प्रेरक बन चुकी है।

कर व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा कर-संग्रह नहीं, कर-निष्ठा है। कर चोरी, अघोषित आय और नकद अर्थव्यवस्था का विस्तार ईमानदार करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डालता है और सामाजिक असमानता को गहरा करता है। इसलिए प्रभावी कर प्रशासन और करदाता-सुविधा के बीच संतुलन अनिवार्य है। सरकार की जिम्मेदारी सरल कानून, स्पष्ट प्रक्रियाएँ और त्वरित शिकायत निवारण सुनिश्चित करना है, वहीं नागरिकों को समझना होगा कि कर से बचना अंततः राष्ट्र और अपने ही विकास से विमुख होना है। लोकतंत्र केवल अधिकारों का उत्सव नहीं, दायित्वों का अनुशासन भी है। जब कर भुगतान राष्ट्रनिर्माण में स्वैच्छिक सहभागिता का संस्कार बन जाएगा, तब अनुपालन दंड के भय से नहीं, जागरूक नागरिकता से स्वतः सुनिश्चित होगा।

राष्ट्र की तकदीर संसदों में जितनी लिखी जाती है, उतनी ही नागरिकों की लेखा-पुस्तिकाओं में भी दर्ज होती है। आयकर दिवस उस मौन प्रतिबद्धता का सम्मान है, जिसके सहारे देश की आकांक्षाएँ आकार पाती हैं। ईमानदारी से अदा किया गया प्रत्येक कर केवल राशि नहीं, आने वाले कल के प्रति एक सार्वजनिक विश्वास-पत्र है। जब यह भावना जनमानस का स्वभाव बन जाएगी, तब कराधान कानून का विषय भर नहीं रहेगा, बल्कि सभ्य नागरिकता की पहचान बन जाएगा। यही चेतना भारत को केवल आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी अग्रणी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करेगी। इस आयकर दिवस पर हम सब मिलकर ईमानदार कर-भुगतान को अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता बनाएं।

स्मार्ट मीटर : बिजली मीटर के विकास का अगला स्वाभाविक कदम

गोविन्द पटेल, (उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज, रायपुर)

आज के दौर में सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास सही और समय पर जानकारी होती है, वह बेहतर निर्णय ले सकता है। स्मार्ट मीटर भी बिजली उपभोक्ता को यही क्षमता देता है। यह उसे अपनी बिजली खपत को समझने, उसका विश्लेषण करने और आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित करने का अवसर प्रदान करता है। मुझे अपनी पुरानी मारुति 800 कार याद आती है। उसमें किलोमीटर मीटर के साथ केवल पेट्रोल इंडिकेटर होता था। उससे केवल इतना पता चलता था कि गाड़ी कितनी चली और कितना पेट्रोल बचा है। लेकिन आज की कारों के स्मार्ट डिजिटल डैशबोर्ड हर पल बताते हैं कि गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है, किस गति पर ईंधन की खपत बढ़ रही है और कितनी दूरी तक चल सकती है। जानकारी बढ़ी है, इसलिए वाहन पर नियंत्रण भी पहले से बेहतर हुआ है।

ठीक ऐसा ही सफर बिजली मीटर का भी है। उन्नीसवीं सदी में जब पहली बार बिजली लोगों के घरों तक पहुंची, तब कई स्थानों पर उपभोक्ताओं से बल्बों की संख्या के आधार पर शुल्क लिया जाता था। बाद में मेकेनिकल बिजली मीटर विकसित हुए। भारत में लंबे समय तक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों का व्यापक उपयोग हुआ। इनमें घूमने वाली डिस्क होती थी, जो बिजली की खपत दर्ज करती थी। एक जमाना था जब बिजलीकर्मी डायरी लेकर घर-घर जाते और रीडिंग नोट करते थे। यह व्यवस्था अपने समय के लिए उपयोगी थी, लेकिन मानवीय त्रुटियों की संभावना बनी रहती थी।

इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए, जिनमें छेड़छाड़ की संभावना काफी कम हुई। फिर मल्टी-फंक्शन डिजिटल मीटर विकसित हुए, जो बिजली खपत के साथ वोल्टेज, अधिकतम मांग (मैक्सिमम डिमांड) जैसी तकनीकी जानकारियां भी दर्ज करने लगे। तुरंत बिल तैयार करने की व्यवस्था भी विकसित हुई। इसके बावजूद एक कमी बनी रही। उपभोक्ता को महीने के अंत में ही पता चलता था कि उसने कितनी बिजली खर्च की। प्रतिदिन अपनी खपत जानने और उसे नियंत्रित करने का अवसर उसके पास नहीं था।

यहीं से स्मार्ट मीटर की आवश्यकता महसूस हुई। वर्ष 2001 में इटली ने बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर का उपयोग शुरू किया। आज दुनिया के अधिकांश विकसित और अनेक विकासशील देशों में स्मार्ट मीटर बिजली व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। पारंपरिक मीटर और स्मार्ट मीटर के बीच सबसे बड़ा अंतर सूचना के प्रवाह का है। स्मार्ट मीटर से डेटा कंपनी के सर्वर तक पहुंच जाता है। जहां यह सुविधा उपलब्ध है, वहां उपभोक्ता भी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी बिजली खपत का विवरण देख सकता है। अर्थात अब बिजली की जानकारी केवल बिजली कंपनी के पास ही नहीं रहती, बल्कि उपभोक्ता के हाथ में भी आ गई है।

स्मार्ट मीटर पहली बार उपभोक्ता को अपनी बिजली खपत को नियमित रूप से देखने और समझने का अवसर देता है। इससे बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होती है और आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता स्वयं भी अपनी खपत का मिलान कर सकता है। उसे केवल महीने के अंत में आने वाले बिल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

भारत सरकार ने वर्ष 2021 में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत देशभर में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ। आज प्रदेश के लगभग 55 लाख उपभोक्ताओं में से 41 लाख से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

स्मार्ट मीटर का कार्य केवल उपभोक्ता की वास्तविक बिजली खपत को दर्ज करना है। उपभोक्ताओं की शंकाओं के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने चार हजार से अधिक घरों में समानांतर चेक मीटर लगाकर दोनों मीटरों की खपत का परीक्षण किया। जांच में दोनों मीटरों की दर्ज खपत समान पाई गई। वर्तमान में बिजली बिल बढ़ने की शिकायतों के विश्लेषण से यह सामने आया है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में एसी, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों के अधिक उपयोग से बिजली की खपत बढ़ जाती है। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष अप्रैल, मई और जून में अधिक गर्मी दर्ज की गई। ऐसे में अनेक उपभोक्ताओं की बिजली खपत बढ़ी, जिसका सीधा प्रभाव उनके बिजली बिल पर पड़ा। कई उपभोक्ता 400 यूनिट की सीमा पार कर एम-ऊर्जा (हाफ बिजली) योजना के दायरे से बाहर हो जाते हैं। वहीं कुछ मामलों में स्वीकृत भार से अधिक लोड उपयोग करने पर अधिकतम मांग (मैक्सिमम डिमांड) से संबंधित प्रभार भी बिल में जुड़ जाता है। इन परिस्थितियों को स्मार्ट मीटर से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।

स्मार्ट मीटर होने से ही उपभोक्ता अपने छतों पर लगे सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से रूफटॉप सोलर अपनाकर उपभोक्ता अपनी बिजली आवश्यकता का बड़ा हिस्सा स्वयं पूरा कर सकते हैं। इससे बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है और कई मामलों में यह लगभग शून्य तक भी पहुंच सकता है। आज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास का आधार विश्वसनीय विद्युत व्यवस्था है। बिजली केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है। बिजली की चोरी और दुरुपयोग का नुकसान अंततः पूरे समाज को उठाना पड़ता है। पारदर्शी और उत्तरदायी विद्युत व्यवस्था हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

स्मार्ट मीटर केवल एक मीटर नहीं, बल्कि पारदर्शी और जवाबदेह बिजली व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह वास्तविक बिजली खपत का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है और उपभोक्ता को अपनी खपत समझने में सहायता करता है। यह उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत की सूचना प्रदान करने का सशक्त माध्यम है, यह बिजली की सूचना का अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि सही सूचना ही आज सबसे बड़ी शक्ति है।

संवाद से सशक्तिकरण तक" : बीएसपी में महिला कर्मियों के लिए शुरू हुई 'सखी संवाद' पहल

कार्यस्थल को सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में नया कदम, स्वास्थ्य, सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता पर होंगे सालभर कार्यक्रम

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र इरढ महिला कर्मचारियों के कार्यस्थल को न सिर्फ सुरक्षित, बल्कि जागरूक, आत्मविश्वासी और संवादपूर्ण बनाने के लिए लगातार नई पहलें कर रहा है। इसी कड़ी में परियोजनाएं विभाग ने 'सखी संवाद' कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला अधिकारी, गैर-अधिशासी कर्मचारी और संविदा महिला कर्मियों के लिए एक साझा मंच है, जहां वे स्वास्थ्य, सुरक्षा, कार्यस्थल की चुनौतियों और व्यक्तिगत विकास पर खुलकर बात कर सकें।

30 महिलाओं ने ली भागीदारी

23 जुलाई 2026 को प्रोजेक्ट्स एक्सपेंशन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य महाप्रबंधक परियोजनाएं उन्मेष भारद्वाज ने किया।

इसमें परियोजनाएं विभाग की लगभग 30 महिला अधिकारी, कर्मचारी और संविदा कर्मी शामिल हुई।

सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन सुश्री जया राय और उनकी टीम ने कार्यस्थल पर प्रभावी संवाद और जागरूकता पर प्रस्तुति दी। वहीं महाप्रबंधक परियोजनाएं सुश्री राधिका श्रीनिवासन, सुश्री नीलू भारद्वाज और सुश्री बोन्या मुखर्जी ने अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पेशेवर विकास पर विचार रखे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अपने अनुभव साझा करने का मंच भी मिला।

कार्यक्रम के दौरान संविदा महिला कर्मियों को पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। विभाग का मानना है कि स्वास्थ्य जागरूकता और जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता महिलाओं के सम्मानजनक कार्य वातावरण का अहम हिस्सा है। 'सखी संवाद' की अवधारणा कायपालक निदेशक परियोजनाएं पीके सरकार के मार्गदर्शन में महिला दिवस 2026 पर विकसित की गई थी। इसके तहत अब पूरे साल महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, कार्यस्थल सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल क्षमता, लैंगिक संवेदनशीलता और प्रेरक संवाद जैसे विषयों पर नियमित कार्यक्रम होंगे।

पहले भी चलीं 'अर्थज्ञान' और 'नई चेतना' जैसी पहलें

इरढ का परियोजना विभाग पहले भी महिला कल्याण के लिए काम करता रहा है। 'अर्थज्ञान' कार्यक्रम के जरिए महिला ठेका श्रमिकों को बैंकिंग, बचत, डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी गई, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें। वहीं 'नई चेतना' अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों में महिला ठेका श्रमिकों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, कार्यस्थल सुरक्षा और श्रम अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। इसमें न्यूनतम वेतन, बोनस, पीएफ, ईएसआईसी और संयंत्र द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। किसी भी संस्थान की प्रगति सिर्फ उत्पादन से नहीं, बल्कि कर्मचारियों विशेषकर महिला कर्मियों के स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सम्मान से तय होती है।

खास खबर

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास, जशपुर की पॉक्सो कोर्ट का फैसला, एक महीने में पूरी हुई जांच

नई दृष्टिबिंदु / जशपुर

जशपुर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने 13 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश जनार्दन खरे ने यह फैसला सुनाया। यह मामला कांसाबेल थाना क्षेत्र का है।

क्या है मामला : पीड़िता की मां ने 2 मई 2026 को थाना कांसाबेल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी पिता पिछले तीन वर्षों से नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपी की पहचान कलेसर विश्वकर्मा, उम्र 42 वर्ष के रूप में हुई है।

एक महीने में पूरी हुई जांच : पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कारर्वाई की। पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ चिकित्सीय परीक्षण, न्यायालयीन कथन और अन्य वैधानिक कार्यवाही पूरी की गई। आरोपी को 2 मई को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जशपुर पुलिस ने इस प्रकरण की विवेचना एक महीने के भीतर पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए। ठोस साक्ष्यों और प्रभावी अभियोजन के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस का बयान : इस संबंध में डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के प्रति जशपुर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा, "ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, समयबद्ध विवेचना और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कठोरतम दंड दिलाना हमारी सवीच्च प्राथमिकता है। समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जशपुर पुलिस निरंतर प्रतिबद्ध है।"

शिवनाथ नदी में नहाने उतरे 8 दोस्तों में से दो बहे, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी

दुर्ग। थाना पुलगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनियारी-पीपरछेड़ी स्थित शिवनाथ नदी में रविवार को जन्मदिन मनाने गए दोस्तों का जश्न उस समय मातम में बदल गया, जब नदी में नहाने के दौरान तेज बहाव में दो किशोर बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तथा तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जानकारी के अनुसार, आठ दोस्त जन्मदिन मनाने के लिए शिवनाथ नदी पहुंचे थे। नहाने के दौरान दो किशोर अचानक गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गए। साथियों के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

जिला सेनानी दिनेश कुमार रावटे के निर्देश पर एसडीआरएफ दुर्ग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गहरे पानी में डीप डाइविंग के माध्यम से सघन तलाश अभियान शुरू किया। रेस्क्यू के दौरान एक किशोर का शव बरामद कर पुलिस को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान रेहान खान (14 वर्ष), पिता नदीम खान, निवासी बॉम्बे आवास, उरला के रूप में हुई है। वहीं दूसरे लापता किशोर की तलाश देर शाम तक जारी रही।

रेस्क्यू अभियान का नेतृत्व एसडीआरएफ प्रभारी धनीराम यादव ने किया। अभियान में भूपेंद्र सिंह, चंद्रप्रताप, राजकुमार यादव, दिलीप, सूरज, राजू महानंद, महेश, रमेश, राजेश नेताम, कुंजेश, दिनेश, शारदा एवं भानुप्रताप सहित एसडीआरएफ के जवानों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लापता किशोर की तलाश में लगातार जुटी हुई है। इस हृदयविदारक घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने लोगों से नदी और जलाशयों में नहाते समय विशेष सावधानी बरतने तथा तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।

महाप्रभु श्री जगन्नाथ के वापसी रथयात्रा में उमड़ी भीड़

सेक्टर-10, गुण्डिचा मंडप में समाजसेवी संजय मिश्रा ने किया छेरा पंहरा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

जगन्नाथ समिति सेक्टर-4 के तत्वाधान में भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी की बाहुड़ा (वापसी) रथयात्रा, सेक्टर-10 के भव्य गुण्डिचा मंडप से निकाली गयी। रथ गुण्डिचा मंडप से निकलकर सेन्ट्रल एवेन्यू होते हुए सेक्टर-4, बोरिया मार्केट स्थित जगन्नाथ मंदिर में पहुँची। बाहुड़ा रथयात्रा मे उद्योगपति एवं समाजसेवी श्री संजय मिश्रा जी ने मुख्य अतिथि के रुप मे छेरा पंहरा का कार्यक्रम सम्पन्न किया।

भिलाई में श्रद्धा और उत्साह के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा

भगवान श्रीजगन्नाथ की पावन बाहुड़ा यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुई। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र तथा देवी सुभद्रा के रथ का दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया।

यात्रा के शुभ अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति प्रो. सचिदानंद शुक्ला ने पारंपरिक 'छेरा पहरा' की रस्म निभाते हुए भगवान के रथ के समक्ष झाड़ू लगाकर विनम्र सेवा का संदेश दिया। इसके बाद भगवान श्रीजगन्नाथ को रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। नगर भ्रमण के दौरान रथ सेक्टर-5 चौक होते हुए श्री मंदिर, सेक्टर-6 स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचा, जहां विशेष पूजा-अचर्ना एवं आरती का आयोजन किया गया। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर भगवान का स्वागत किया तथा "जय जगन्नाथ" के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा।

इस अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के डीन प्रो. अरूप श्रीवास्तव सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए यात्रा के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जताई।

समाजसेवी संजय मिश्रा द्वारा छेरा-पंहरा सम्पन्न

भगवान श्री बलभद्र, माता सुभद्रा तथा महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को पंहडी करते हुए काष्ठ निर्मित सुन्दर व भव्य रथ पर लाया गया। इस वर्ष बाहुड़ा रथयात्रा (वापसी रथयात्रा) के दौरान रथ के समक्ष परम्परा अनुसार छेरा-पंहरा कार्यक्रम, मुख्य अतिथि समाजसेवी श्री संजय मिश्रा जी द्वारा सम्पन्न किया गया। पुरी में यह परम्परा पुरी के महाराज सम्पन्न करते है। छेरा-पंहरा के पश्चात भक्त जनों ने ह्यजय जगन्नाथह्न के उद्घोष के साथ रथ खींचना प्रारंभ किया। समाजसेवी श्री संजय मिश्रा जी ने श्री जगन्नाथ स्वामी जी की पुजा अचर्ना की और भिलाईवासियों के सुख समृद्धि हेतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी जी से आशीर्वाद मांगो इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में सेफी, चेयरमैन एवं बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार बंछोर तथा जगन्नाथ समिति के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सतपथी एवं महासचिव सत्यवान नायक विशेष रुप से उपस्थित थे।

महाप्रभु को लगा छप्पन भोग

गुंडीचा मंडप, सेक्टर 10 में श्री त्रिनाथ साहू के संयोजन में महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी जी के समक्ष छप्पन भोग लगाने का आयोजन किया गया। भक्तों द्वारा बिना प्याज लहसुन के विभिन्न भोग घर से बनाकर गुंडिचा मंडप लाया गया। भक्तों द्वारा लाए गए छप्पन भोग को प्रभु के समक्ष भोग लगाया गया। पूजा अचर्ना कर महाप्रभु को भोग समर्पित किया गया। अंत में भोग का वितरण भक्तों के मध्य किया गया। 156 श्रद्धालुओं के कुल 306 भोग लगाया गया।

भक्ति के धुन में नाचते-गाते भक्त

झांझ, मंजीरे, ढ़ोल, मृदंग बजाते कीर्तन दल तथा भक्ति संगीत के धुन में नाचते-गाते भक्त जनों ने भाव विभोर होकर रथ खींचा। सेन्ट्रल एवेन्यु में महाप्रभु के दर्शन व पूजा अचर्ना हेतु हजारों की संख्या में श्रद्धालु सड़क के दोनों ओर खड़े थे। महाप्रभु का रथ सेन्ट्रल एवेन्यु में पहुँचते ही रथ खींचने व दशर्नार्थ भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े।

विभिन्न संस्थाओं ने किया भव्य स्वागत

इस पूरे यात्रा के दौरान अन्न प्रसाद व गजामूंग के प्रसाद का वितरण किया गया व विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग संस्थाओं व समाज द्वारा रथ का भव्य स्वागत किया। पूर्व पार्षद श्री कोरमा राव एवं पूर्व पार्षद श्री जे श्रीनिवास राव के साथ न्यू आजाद गणेशोत्सव समिती के सभी सदस्यों ने सेक्टर-2 चौक में भारी आतिशबाजी के संग रथयात्रा का भव्य स्वागत किया।

अन्न व गजामूंग प्रसाद का वितरण

विभिन्न स्थानों पर पंडाल लगा कर श्रद्धालुओं को भोग व शर्बत आदि का वितरण किया गया। रथ का संचालन वृंदावन स्वांई एवं श्री बी सी बिस्वाल द्वारा किया गया। 7 मिलियन टन चौक पर से.-6 व से-4 के रथों का मिलन हुआ तथा दोनों के पुजारियों व पदाधिकारियों ने एक-दूसरे के रथ पर जाकर भगवान की पूजा अचर्ना की। रथयात्रा के विभिन्न पूजा कर्म पण्डित सर्वश्री पितवास पाढ़ी द्वारा विधि विधान से सम्पन्न किया गया।

सफल बनाने में इनका है योगदान

इस उत्सव को सफल बनाने में जगन्नाथ समिति के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सतपथी व महासचिव सत्यवान नायक सहित समिति के पदाधिकारी सर्वश्री त्रिनाथ साहू, भीम स्वांई, बी सी बिस्वाल, अनाम नाहक, डी त्रिनाथ, वृंदावन स्वांई, कैलाश पात्रो, कालू बेहरा, बसंत प्रधान, प्रकाश स्वांई, रवि स्वांई, बीस केशन साहू, कवि बिस्वाल, निरंजन महाराणा, रंजन महापात्र, जगन्नाथ पटनायक, निरंजन महाराणा, राजू बेहरा, सीमांचल बेहेरा, वी के होता, एस दलाई, लखन बिस्वाल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

विरोध प्रदर्शन | मेहनतकश आवास अधिकार संघ और मुक्ति मोर्चा ने सरकार से मांगे पूरी करने की मांग की

जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन की अनदेखी, भिलाई में मजदूरों ने निकाला मशाल जुलूस

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

मेहनतकश आवास अधिकार संघ एवं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय से चल रहे छात्रों के धरने की मांगों को केंद्र सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। इसके विपरीत संसद मार्च के दौरान हजारों छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस छोड़ी गई।

संगठनों ने कहा कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल वीडियो में पुलिस की बर्बरता साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में महिला प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, दुर्व्यवहार और कपड़े फाड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। इसे बेहद चिंताजनक बताते हुए दोनों संगठनों ने कहा कि यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

विज्ञप्ति में कहा गया कि नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला अब जगजाहिर हो चुका है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में संबंधित मंत्री

धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन सत्ता के अहंकार के कारण छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा। देश के कई राज्यों में छात्रों के समर्थन में जनसैलाब उमड़ रहा है।

संगठनों ने जानकारी दी कि सोनम वांगचुक ने सरकार से लिखित सहमति के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है, लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। उन्होंने मांग की कि सरकार छात्रों की मांगों को शीघ्र पूरा करे और दमनात्मक कारर्वाई तुरंत बंद करे।

छात्र आंदोलन के समर्थन में शनिवार शाम भिलाई के अस्पताल सेक्टर क्षेत्र से मजदूरों ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस सेक्टर-9 चौक में पहुंचकर नारेबाजी के साथ संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम में नारायण राव, लोईमू से सुरेंद्र मोहंती, जन संघर्ष मोर्चा से वी एन प्रसाद राव, महिला मुक्ति मोर्चा से नीरा डेहरिया, अरुणा, संजना, मन्नू, ब्रह्मा, सुंदरिया, के. मैरी, कलादास डेहरिया, प्रेम किशन सहित सैकड़ों मजदूर और नागरिक उपस्थित रहे।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय मे मामला क्रमांक : 202607101000167

विषयः- अ-5
मामले की श्रेणीः- राजस्व
सनः- 2025-2026
कोहका प.ह.न. 00045 [(हे0)]
पक्षकारों का विवरण आवेदक पक्षकार सोहन लाल, अनावेदक पक्षकार -

-:: ईश्तहार ::

आवेदक-सोहन लाल पिता/पति/विभाग-बृजलाल निषाद पता-कोहका द्वारा ग्राम कोहका प.ह.न. 45 रा.नि.म. कोहका, तहसील व जिला - दुर्ग की भूमि पुराना ख.न. 181/3 का टू. रकबा 5 डिसमील भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता फेरु आ. बिस्म्भर रावत से क्रय किया गया था। नामांतरण पश्चात निर्मित खसरा न. 181/97 रकबा 0.020 है. ऋण पुस्तिका में आवेदक का नाम दर्ज है! किन्तु बंदोबस्त के पश्चात वतर्मान राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। बंदोबस्त के दौरान हुई त्रुटी को सुधार किये जाने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है!

अतएव इस संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 11/08/2026 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयवधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगान

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17/07/2026 को जारी किया जाता है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

(रा.प्र.कं.../अ/6 वर्ष 2025-26)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक - हिमांशु तिवारी आ./ध.प. हरेन्द्र तिवारी अन्य 1 निवासी- नेहरू नगर भिलाई द्वारा ग्राम- कोहका प.ह.नं. 4.5 रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 2149/22. रकबा 0.010 हे. 1000 वर्गफीट भूमि को रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर दिनांक 21/20/2024 के आधार पर विक्रेता श्रीमती हेमिन बाई सिन्हा ध.प. श्री नरसिंग सिन्हा से क्रय किया गया है, कि रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत आवेदन पत्र मय बैनांमा की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 13/8/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/07/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

राम गोपाल वर्मा की तारीफ पर गदगद हुईं यामी गौतम

अभिनेत्री यामी गौतम इन दिनों 'आर्टिकल 370' से मिले राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। अभिनेत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए मनोरंजन जगत में बिताए लंबे सफर को सबसे बड़ा शिक्षक बताया। दरअसल, यामी की इस जीत पर निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए बधाई दी थी, जिस पर यामी ने खुशी जाहिर करते हुए उनका धन्यवाद किया। अभिनेत्री ने अपने सफर को याद करते हुए टेलीविजन की दुनिया को 'सबसे बड़ा टीचर' बताया। अभिनेत्री ने लिखा, 'बहुत-बहुत धन्यवाद, सर। आपके शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। यह सफर सच में मेरे लिए सबसे बड़ा शिक्षक रहा है और आपके प्रोत्साहन व सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूं। आगे भी सीखते, आगे बढ़ते और अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहने की कोशिश जारी रहेगी।'

अभिनेत्री यामी गौतम ने टेलीविजन इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत कर खुद को हिंदी सिनेमा की सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। बता दें कि 'आर्टिकल 370' 2024 में रिलीज हुई एक राजनीतिक एक्शन-थ्रिलर फिल्म थी। यह फिल्म जम्मू-कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जे को निरस्त करने और राज्य से आतंकवाद के खात्मे की ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में अभिनेत्री यामी गौतम ने 'जूनी हक्सर' नामक एक खुफिया (इंटेलिजेंस) अधिकारी की भूमिका अदा की थी और प्रियमणि ने पीएमओ सचिव 'राजेश्वरी स्वामीनाथन' की मुख्य भूमिका निभाई थी। इनके अलावा अरुण गोविल (प्रधानमंत्री) और किरण करमाकर (गृह मंत्री) के किरदार में नजर आए थे।

इसका निर्देशन आदित्य सुहास जाम्भले ने किया था। इसकी पटकथा 2016 की कश्मीर अशांति और अनुच्छेद 370 को हटाने के गुप्त मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद, यह फिल्म जी5 और नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही थी। फिल्म ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 'सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म' का पुरस्कार जीता और यामी गौतम को 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का पुरस्कार मिला।

महिमा मकवाना ने बताई इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती

अभिनेत्री महिमा मकवाना ने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभाए हैं और अब वह अपनी आने वाली वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अभिनय की दुनिया जितनी ग्लैमरस दिखाई देती है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी होती है। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में काम के घंटे तय नहीं होते और कई बार कलाकारों को लगातार व्यस्त रहना पड़ता है। ऐसे में मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए एक रूटीन होना बेहद जरूरी है। आईएएनएस से खास बातचीत में महिमा ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक खास तरह का रूटीन हमेशा जरूरी होता है, ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहे. अभिनय ऐसा पेशा है, जिसमें कलाकार को हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करनी पड़ती है। इसमें आपको हर समय शांत मानसिकता में रहना पड़ता है, इसलिए किसी भी तरह की एक तय व्यवस्था बहुत जरूरी है और अब इसे लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है।'

महिमा ने कहा, ''मनोरंजन जगत में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यहां काम के दिन और छुट्टियों का कोई निश्चित नियम नहीं होता। इस क्षेत्र में कलाकारों को कई बार लंबे समय तक काम करना पड़ता है और शूटिंग शेड्यूल लगातार बदलते रहते हैं। ऐसे में अपने निजी जीवन और काम के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती होती है, जिससे काम भी प्रभावित न हो और आपकी मानसिक सेहत भी ठीक रहे।'' काम के घंटों और इंडस्ट्री में बदलाव को लेकर महिमा ने कहा, ''अब इस विषय पर पहले से ज्यादा बातचीत हो रही है। हर कलाकार की स्थिति अलग होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने करियर में कहां हैं। आप अपनी बात किस तरह रख सकते हैं और फिल्म निर्माताओं के साथ किस तरह तालमेल बना सकते हैं। हर किसी के लिए स्थिति अलग होती है।''

उन्होंने कहा, ''किसी भी फैसले में सिर्फ अपनी सुविधा को नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूरी टीम के नजरिए को भी समझना जरूरी है। किसी फिल्म या शो में कई लोगों की मेहनत और पैसा जुड़ा होता है, इसलिए ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो सभी के लिए सही हो।'' वर्क फ्रंट की बात करें तो महिमा मकवाना जल्द ही 'मुसाफिर कैफे' में नजर आएंगी। इस प्रोजेक्ट में उनके साथ अभिनेता विक्रांत मैसी और वेदिका पिंटो भी मुख्य भूमिका में हैं।

नितांशी गोयल ने पूरी की 'तक्षाकुडू' की शूटिंग

फिल्म 'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल अपनी अपकमिंग फिल्म 'तक्षाकुडू' को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। उन्होंने सेट से कई बीटीएस तस्वीरें शेयर की हैं। नितांशी ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें देखा जा सकता है कि वह दुल्हन की तरह सजी हैं। एक दूसरी तस्वीर में वह कुत्ते के सिर से अपना सिर लगा रगा रही हैं। एक और तस्वीर में वह आनंद देवरकोंडा के साथ पोज दे रही हैं। एक और तस्वीर में वह फिल्म की टीम के साथ नजर आ रही हैं।

तस्वीरें शेयर करते हुए नितांशी ने लिखा 'तक्षकुडू की शूटिंग पूरी कर ली है। यह सफर बहुत अच्छा रहा। सेट पर हर दिन मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसे अपने घर ले जा सकूं। बहुत अच्छी यादें बनाई। बहुत अच्छे लोग मिले। एक ऐसी भाषा सीखी, जिससे प्यार हो जाए। फिल्म में अपने किरदार के बहुत पास रहूंगी।' आपको बता दें कि नितांशी गोयल की अपकमिंग फिल्म 'तक्षाकुडू' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इसमें वह 'करुणा' नाम की एक लड़की का किरदार निभा रही हैं। इसमें उनके साथ आनंद देवरकोंडा हैं। इसके निर्देशक विनोट अनंतोजु हैं।

नितांशी गोयल साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'लापता लेडीज' में नजर आई थीं। इसमें उन्होंने फूल कुमारी का किरदार निभाया था, जिसकी काफी तारीफ हुई थी। बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें आईफा अवॉर्ड मिला था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी।

अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक से अलग हुए आमिर खान

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान भारतपे के पूर्व को-फाउंडर और बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक से बाहर हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के डायरेक्टर राहुल मोदी के साथ क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से आमिर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का फैसला किया है। पहले खबर थी कि आमिर इस फिल्म में अश्नीर ग्रोवर का किरदार निभाने वाले थे और उनके साथ श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में थीं। आमिर के फिल्म छोड़ने के बावजूद मेकर्स इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखेंगे। अब श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी अश्नीर के रोल के लिए किसी युवा एक्टर की तलाश कर रहे हैं।

क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से अलग हुए आमिर

आमिर खान को स्टार्टअप्स की दुनिया काफी पसंद है। वे अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक को लेकर काफी उत्सुक थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया था और इसे अपने हिसाब से तैयार करने की कोशिश की। हालांकि, स्क्रिप्ट और फिल्म के डायरेक्शन को लेकर डायरेक्टर राहुल मोदी और आमिर के विचार अलग थे। लगातार बातचीत के बाद भी जब सहमति नहीं बनी, तो आमिर ने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। मेकर्स को नए यंग एक्टर की तलाश आमिर खान के हटने के बाद भी बायोपिक पर काम बंद नहीं हुआ है। डायरेक्टर राहुल मोदी और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर फिल्म को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब मेकर्स अश्नीर ग्रोवर के रोल के लिए किसी युवा एक्टर की तलाश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स की इंडस्ट्री के दो से तीन बड़े युवा एक्टर्स से बात चल रही है और जल्द ही मुख्य किरदार के नाम पर मुहर लग सकती है। मार्च 2027 में शुरू होने वाली थी फिल्म की शूटिंग

शुरुआती योजना के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2027 में शुरू होनी थी। आमिर खान निर्देशक आशुतोष गोवारिकर के साथ अपनी पीरियड ड्रामा फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद इस बायोपिक का काम शुरू करने वाले थे। हालांकि, अब कास्टिंग में बदलाव होने के बाद शूटिंग शेड्यूल पर भी असर पड़ सकता है।

फिल्म में एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन भी संभालेंगी श्रद्धा

इस बायोपिक में श्रद्धा कपूर अहम भूमिका में नजर आएंगी। वे फिल्म में अश्नीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर का किरदार निभा सकती हैं। इसके साथ ही श्रद्धा कपूर एक बड़े स्टूडियो के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं। एक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर यह फिल्म श्रद्धा के करियर का बड़ा प्रोजेक्ट मानी जा रही है।

ऑडियंस के पास अब बहुत चॉइस अच्छा कॉन्टेंट देंगे तभी वो आपके पास आएंगी

अन्नू कपूर उन कलाकारों में से हैं, जिन्हें दर्शक लंबे समय से स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर चाहे वह रिएलिटी शो 'अंताक्षरी' में होस्ट रहे हों या 'विकी डोनर' और 'ड्रीम गर्ल' में उनके बेहतरीन कॉमेडी रोल, वह हर अंदाज में जंचते हैं। फिल्मी दुनिया में साढ़े चार दशक लंबा समय बिता चुके अन्नू कपूर कहते हैं कि मुझे इस दुनिया में जो मिला वह काफी है। मैं कहूंगा कि मेरे भाग्य में जितना था, उतना ही मिला। साल 2012 में आई 'विकी डोनर' में अपने अभिनय के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले अन्नू मानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई सीरियस फिल्में ज्यादा करती हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या हमेशा से कॉमेडी फिल्में दर्शकों की पसंदीदा रही हैं? तो उन्होंने कहा, 'नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ताज्जुब करेंगे कि जिन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई की है और जो कॉन्टेंट आधारित फिल्में रही हैं, उनमें से 80 फीसदी फिल्में ट्रैजिडी और सीरियस जॉनर की रही हैं। अगर आप ऑस्कर का इतिहास देखेंगे, तो सवा सौ सालों में सिर्फ दो कॉमेडी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला है। अगर ऐसा होता तो जिन डायरेक्टर्स ने सिर्फ कॉमेडी फिल्में बनाई हैं, उनका नाम भारत के बेस्ट डायरेक्टर्स में आता, लेकिन उनका नाम टॉप 50 में भी नहीं है।'

करीब पांच दशक पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई के दौरान अन्नू ने दिल्ली में भी काफी वक्त गुजारा। जब उनसे कुछ यादें साझा करने को कहा गया, तो उन्होंने वह मजेदार किस्सा साझा किया, जब वह एक बार में 23 रोटियां खा गए थे। बकौल अन्नू, 'अभी जब मैं इंटरव्यू के लिए आ रहा था, तो रास्ते में रेपयूजी मार्केट से गुजरा। तब मुझे वो जवानी के दिन याद आ गए, जब मेरे सामने खाने के लाले होते थे। मुझे आज भी याद है वह मई-जून की चिलचिलाती गर्मी का दिन इसी रेपयूजी मार्केट में, जब दो-तीन दिन से पेट में कुछ ठीक से गया नहीं था। उस दौरान कहीं से काम के बदले 75 रुपए का चेक मिला। इतना भूखा था मैं कि मैं उस दिन 23 रोटियां खा गया था। उस दिन 23 रोटियां, दो टिक्की मक्खन की और एक रुपए का नत्थू स्वीट्स से छोले का कुल्हड़ और दाल फ्राई खा के मैं मस्त हाथी की तरह चलता हुआ पैदल अपने हॉस्टल पहुंचा, क्योंकि अब ऑटो का किराया नहीं बचा था। हॉस्टल जाकर मैं नहाया और सो गया। उस दिन मुझे जो नींद आई, तो फिर मैं सीधा रात को साढ़े नौ बजे उठा।'

ऑडियंस के सामने कॉन्टेंट की कमी नहीं है

अन्नू जल्द अपनी नई फिल्म 'उत्तर दा पुत्तर' में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनका किरदार हमेशा भविष्य में होने वाली चीजों की चिंता करता है। जब उनसे पूछा गया कि इस फिल्म को उन्होंने क्या सोचकर हां किया, तो उन्होंने जवाब दिया, 'इसका टॉपिक वाकई अच्छा है और अच्छे कॉन्टेंट के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का कोई कोई भी एक्टर ना कहेगा, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि हमारी ऑडियंस के पास इतनी चॉइस आ चुकी हैं कि आप अच्छा कॉन्टेंट देंगे तभी वो आपके पास आएंगी। अब गली-गली के मोड़ पर इतने कॉन्टेंट क्रिएटर्स हो गए हैं। तो यह कॉम्पटीशन पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा है। एक इसका पहलू यह भी है कि अब लोग अच्छा कॉन्टेंट लेकर आएंगे।'

मैंने गुरु नानक जी से सीखा है

जब हमने अन्नू से पूछा कि क्या कभी उन्हें भविष्य की चिंता नहीं हुई, तो उन्होंने बताया, 'मुझे भय जैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सद्गुरु श्री नानक देव जी से एक सीख ली है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जब बाबा नानक 12 साल के थे तो घर से गायब हो गए थे। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बालक नानक कहां चले गए। जब उनके लिए तलाश शुरू हुई, तो वह एक श्मशान में मिले। जब गांव वालों ने पूछा कि आप मरघट यानी मरने के घर में क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह कोई मरने का घर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां आकर कोई मरता नहीं है। यहां तो लोग मरकर आते हैं। और जिस घर को, जिस जगह को तुम घर की निशानी बोल रहे हो, वहां पर लोग मरते हैं। मरघट तो असलियत में वह है। यहां तो लोग चार लोगों के कंधे का सहारा लेकर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चार लोगों का सहारा लेकर क्यों आऊं। इतना कमजोर क्यों बनूं? तो मैं पहले यहां आकर बैठ गया। इससे पता चलता है कि उन्होंने मृत्यु को वैसे ही स्वीकार किया जैसे जीवन को। इसलिए मुझे भी कोई डर की बात नहीं है।'

कांग्रेस की एकजुटता का असर : भाजपा कार्यकर्ता पर हुई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

खुज्जी की राजनीति में नया मोड़, संगठन की ताकत से प्रशासन पर बना दबाव

नई दृष्टिबिंदु / छुरिया

लंबे समय से विवादों में घिरे एक भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बाद खुज्जी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेताओं की अभूतपूर्व एकजुटता और सामूहिक दबाव के कारण प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा।

वर्तमान विधायक भोलाराम साहू, पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू और जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर मोर्चा संभाला। इस प्रदर्शन को राजनीतिक गलियारों में संगठन की ताकत और जनदबाव की जीत के रूप में देखा जा रहा है।

संगठित प्रदर्शन से प्रशासन पर दबाव

कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी की लगातार बनी रणनीति और एकजुटता के कारण ही प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम से यह संदेश गया है कि जब संगठन एकजुट होकर मैदान में उतरता है तो उसका असर प्रशासनिक निर्णयों तक दिखाई देता है।

प्रदर्शन में विधायक भोलाराम साहू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन यादव, पूर्व विधायक छन्नी चंदू चुम्मन साहू, राहुल तिवारी, जावेद मेमन, तरूण सिन्हा, ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू, ललित साहू, पार्षद रोशन रजक, पार्षद सोनू खान, पार्षद मनोज यादव, पूर्व पार्षद राधेश्याम ठाकुर, पार्षद वसीम खान, पार्षद भावना ठाकुर, शकील कुरेशी और अमित अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसी शामिल रहे।

पार्टी के भीतर भी चल रही चर्चा

हालांकि कांग्रेस की एकजुटता की तारीफ के साथ ही पार्टी के अंदरूनी हलकों में पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू की कार्यशैली को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों का कहना है कि कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके रवैये से दूरी बनानी शुरू कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जहां सामूहिक एकता से संगठन मजबूत हुआ है, वहीं कुछ नेताओं की व्यक्तिगत कार्यशैली पार्टी के भीतर असहजता का कारण बन रही है।

कुल मिलाकर भाजपा कार्यकर्ता पर हुई कार्रवाई ने खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। कांग्रेस इसे अपनी संगठनात्मक ताकत और जनदबाव की जीत मान रही है।

खास खबर

नगर निगम द्वारा नागरिकों सुविधाओं के लिए किया जा रहा बेहतर कार्य

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

नगर पालिक निगम राजनांदगांव द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सफाई, जल निकासी, सड़क मरम्मत, पौधरोपण, मवेशी नियंत्रण तथा अधोसंरचना सुधार से संबंधित विभिन्न कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है। नगर निगम की टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी कचरा संग्रहण स्थलों एवं रिक्त भूमि पर डाले गए कचरे की नियमित सफाई जेसीबी एवं टिप्पर के माध्यम से की जा रही है। साथ ही नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं डालने के लिए लगातार समझाइश भी दी जा रही है। खैरागढ़ रोड सहित अन्य क्षेत्रों में भी डम्प कचरे का नियमित उठाव किया जा रहा है।

वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए बड़े नालों, नालियों एवं जल निकासी मार्गों की नियमित सफाई कराई जा रही है। जिला अस्पताल के सामने स्थित नाले तथा अस्पताल परिसर के आसपास की नालियों की विशेष रूप से सफाई कराई गई है। जहां आवश्यक है, वहां कच्ची नालियां बनाकर जल निकासी सुनिश्चित की जा रही है। नया बस स्टैण्ड, नगर निगम कार्यालय परिसर एवं शीतला मंदिर क्षेत्र में भी जलभराव की स्थिति बनने पर त्वरित निकासी की व्यवस्था की जा रही है। स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए रानी सागर क्षेत्र में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया गया है तथा अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

नगर निगम द्वारा शहर की जर्जर सड़कों के संधारण एवं मरम्मत के लिए पेचवर्क कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आगामी गणेश उत्सव एवं वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वार्डों में सड़क सुधार कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। डामर उपलब्ध होते ही शेष सड़कों का डामरीकरण भी कराया जाएगा। चौपाटी, रानी सागर मार्ग तथा चिखली तालाब के किनारे स्थित सड़क की मरम्मत एवं संबंधित कार्य भी प्रक्रियाधीन हैं। शहर में विद्युत सुरक्षा एवं सुचारू प्रकाश व्यवस्था के लिए जर्जर विद्युत पोल हटाने संबंधी प्रस्ताव विद्युत मंडल को भेजे गए हैं। जिला अस्पताल के समीप नाली के बीच स्थित विद्युत पोल को हटाने की प्रक्रिया भी विद्युत विभाग द्वारा की जा रही है। बारिश के कारण शॉर्ट सर्किट से प्रभावित स्ट्रीट लाइटों का सुधार वर्षा थमते ही किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन मवेशी पकड़ने का अभियान संचालित कर उन्हें कांजी हाउस पहुंचाया जा रहा है। रात्रिकाल में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मवेशियों को सड़कों से हटाने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। शहर में चिन्हित जर्जर भवनों के स्वामियों को नोटिस जारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला अस्पताल कॉलोनी एवं उद्योग विभाग के जर्जर भवनों को खाली कराने की प्रक्रिया जारी है, जिसके पश्चात नियमानुसार उन्हें हटाया जाएगा। नागरिक सुविधाओं के विस्तार के तहत पुराने एवं नए बस स्टैण्ड में सार्वजनिक शौचालयों का नियमित संचालन किया जा रहा है। वहीं गोलबाजार में निर्मित अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय के संचालन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इसे आमजन के लिए प्रारंभ किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम ने इस वर्ष वर्षा ऋतु में लगभग 10 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। डिवाइडरों, स्टेट स्कूल उद्यान सहित विभिन्न स्थलों का चयन कर पौधरोपण की तैयारियां की जा रही हैं। गर्मी के कारण प्रभावित पौधों के संरक्षण के लिए नियमित रूप से टैंकरों के माध्यम से सिंचाई भी की जा रही है। गुरुद्वारा के समीप बुढ़ासागर क्षेत्र में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अधूरे कार्य पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर भुगतान रोका गया है तथा वैधानिक कार्रवाई करते हुए नई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम द्वारा शहर की स्वच्छता, जल निकासी, सड़क सुधार, हरित विकास तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से लगातार कार्य किया जा रहा है। नागरिकों के सहयोग से राजनांदगांव को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित शहर बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

जमीन पर बैठकर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने सुनी ग्रामीणों की बात, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात

सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही-उप मुख्यमंत्री

नई दृष्टिबिंदु / कबीरधाम

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के अपने विधानसभा क्षेत्र के सहसपुर लोहारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम भेंड्रा नवागांव और पीरचाटोला में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल होकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में ग्रामीणों के बीच जमीन में बैठकर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं तथा कई मांगों पर मौके पर ही स्वीकृति और घोषणाएं करते हुए विकास कार्यों की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम भेंड्रा नवागांव में आयोजित कार्यक्रम से ग्राम बोटेसुर से नवागांव तक एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क निर्माण कराने की घोषणा की। वहीं ग्राम पीरचाटोला में 5.20 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण तथा वीबीजीरामजी योजना के तहत पुलिया निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत कराने की घोषणा की।

ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और विकास कार्यों के लिए निरंतर स्वीकृति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि भेंड्रा नवागांव, बोटेसुर के गांवों में सामुदायिक भवन, सीसी रोड, बोर खनन, रंगमंच, आहता निर्माण तथा आंतरिक विद्युतीकरण जैसे अनेक कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सूरजपुरा पंचायत में 51 लाख रुपये की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक स्टेडियम में नियमित खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हों तथा आसपास के 15 से 20 गांवों के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि युवाओं को सकारात्मक दिशा मिल सके।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजपुरा और धनौरा सहित क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि पीरचाटोला में 40, सूरजपुरा में 57, पेण्ड्रातराई में 61, बैगापारा में 65 तथा बोटेसुर में 75 आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के गठन के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई थी और बीते ढाई वर्षों में 11 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह डेयरी, दुग्ध उत्पादन और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यदि समूह कार्ययोजना बनाकर आगे आते हैं तो शासन हर संभव सहयोग करेगा। उन्होंने क्षेत्र में जैविक खेती की व्यापक संभावनाओं का उल्लेख करते हुए किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि केवल भवन और सड़क निर्माण ही विकास नहीं है, बल्कि गांव की आर्थिक गतिविधियों, कृषि, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर के वनांचल क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां किसान बिना रासायनिक खाद के सफलतापूर्वक जैविक खेती कर रहे हैं और बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। विद्युत व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था के लिए गांव और खेतों के फीडर अलग करने का कार्य कराया गया है। साथ ही पुराने बकाया बिजली बिलों का भी शासन की योजनाओं के माध्यम से समाधान किया जा रहा है।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरिता संतोष मिश्रा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा पटेल, जनपद उपाध्यक्ष अशोक पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मेडिकल कॉलेज में एचआईवी एड्स-जागरूकता, अधिकार और सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के मेडिसिन विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज भवन के सेमीनार हॉल में एचआईवी एड्स-जागरूकता, अधिकार और सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमीनार में तकनीकी एवं वैज्ञानिक सत्र के दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए गए।

शासन द्वारा एचआईवी एड्स पीड़ितों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सेवाओं और योजनाओं की जानकारी दी। सेमीनार में एचआईवी का परिचय एवं मूलभूत बातें, एचआईवी एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 2017, पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस सहित अन्य विषयों के संबंध में जानकारी दी गई। सेमीनार में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।

सेमीनार में अधिष्ठाता डॉ. पी. एम. लुका, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन, संयुक्त निदेशक-सह-अस्पताल अधीक्षक डॉ. अतुल मनोहर राव देशकर, उप अस्पताल अधीक्षक डॉ. पवन जेठानी, जिला नोडल अधिकारी एचआईवी एड्स डॉ. अल्पना लूनिया, विभागाध्यक्ष मेडिसिन एवं नोडल अधिकारी, एआरटी सेंटर डॉ. एनके तिर्की, सहायक निदेशक राज्य एड्स नियंत्रण समिति श्रीमती रमा पटेल, उप निदेशक राज्य एड्स नियंत्रण समिति सुश्री भाग्यश्री वर्मा, डॉ. प्रकाश खूंटे सहित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एआरटी स्टाफ, आईसीटीसी स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

तीसरी मेरिट सूची के बाद भी कॉलेजों में खाली रहीं सीटें

राजनांदगांव। जिले के महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश के लिए तीसरी मेरिट सूची जारी होने के बावजूद कई पाठ्यक्रमों में सीटें अब भी खाली हैं। जिले के सबसे बड़े स्वशासी दिग्विजय महाविद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य संकाय की बड़ी संख्या में सीटों पर अब तक प्रवेश नहीं हो सका है। महाविद्यालय प्रबंधन के अनुसार इन पाठ्यक्रमों में अब तक करीब 60 प्रतिशत ही दाखिले हुए हैं। सबसे अधिक असर बीएससी (गणित) और बीकॉम पाठ्यक्रमों में देखने को मिल रहा है, जहां अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों ने प्रवेश नहीं लिया।

कलेक्टर के निर्देशन में हाफ नदी पुर्नजीवन अभियान को मिलेगी नई गति

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशन में जिले में विकसित भारत जी-राम-जी अभियान के अंतर्गत हाफ नदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन को जनआंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 25 जुलाई 2026 को विकासखंड नवागढ़ के ग्राम अंधियारखोर में मैदानी कार्यकर्ताओं (फील्ड फंक्शनरी) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रांसेक्ट वॉक एवं व्यापक जनजागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य हाफ नदी के पुनर्जीवन कार्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थानीय सहभागिता एवं प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से गति प्रदान करना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ एवं मैदानी अमले को नदी संरक्षण एवं पुनर्जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण, कैचमेंट क्षेत्र का विकास, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, नदी तटों की सुरक्षा, मृदा एवं जल संरक्षण उपायों सहित नदी आधारित पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही मैदानी स्तर पर कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन एवं विभागीय समन्वय पर भी विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा।

कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित ट्रांसेक्ट वॉक के दौरान अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, मैदानी अमला एवं ग्रामीणजन हाफ नदी के विभिन्न हिस्सों का संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान नदी में गाद जमाव, जल प्रवाह में अवरोध, अतिक्रमण, अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति, तट संरक्षण, जल निकासी मार्ग, उपचार योग्य स्थलों तथा पुनर्जीवन की संभावनाओं का स्थल पर ही अवलोकन

किया जाएगा। इसके आधार पर नदी पुनर्जीवन के लिए आवश्यक कार्यों की प्राथमिकता तय कर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर उनके सुझाव एवं अनुभव भी प्राप्त किए जाएंगे, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सके।

ग्राम स्तर पर आयोजित जनजागरूकता अभियान के माध्यम से नागरिकों को जल संरक्षण के महत्व, वर्षा जल संचयन, सोक पिट निर्माण, वृक्षारोपण, जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने, प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को नदी एवं नालों में नहीं डालने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान के दौरान आगामी विशेष श्रमदान, पौधरोपण एवं नदी संरक्षण गतिविधियों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया जाएगा।

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि जल संरक्षण केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। हाफ नदी जिले की महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है, जिसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिला स्व-सहायता समूहों, किसानों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने और जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आग्रह किया है।

ग्रामीणों को सुविधाएं अमलीडीह से कामनबोड़ तक बनेगी 1.40 किमी लंबी सड़क, मार्ग में 5 पुलियों का भी होगा निर्माण

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 2 करोड़ की लागत के सड़क निर्माण का किया भूमिपूजन

नई दृष्टिबिंदु / कबीरधाम

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम अमलीडीह से कामनबोड़ तक 2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 1.40 किलोमीटर सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क का निर्माण क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांग रही है, जिसके पूरा होने से ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने शीतला माता मंदिर में भवन निर्माण के लिए 6.50 लाख रुपये की घोषणा कर ग्रामीणों को एक और सौगात दी।

भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्माण एजेंसी एवं ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क, पुल-पुलिया सहित सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं, जिससे क्षेत्रवासियों को लंबे समय तक इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं आम जनता की सुविधा के लिए बनाई जा रही हैं, निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सड़क, आवास, बिजली, सिंचाई और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के कार्य को प्राथमिकता से आगे बढ़ा रही है। सरकार बनने के बाद प्रदेशभर में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है, जिससे हजारों गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अमलीडीह सहित कुरुवा पंचायत के अन्य आश्रित गांवों में पिछले दो वर्षों के दौरान 255 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई है। इससे जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आवास के साथ-साथ गांवों में आधारभूत सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अमलीडीह में सड़क और बिजली के अलावा सीसी रोड, चेक डैम सहित अनेक विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों के पूरा होने से गांव में आधारभूत अधोसंरचना मजबूत होगी, कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक गांव बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित होकर आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बने।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरिता संतोष मिश्रा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा पटेल, जनपद उपाध्यक्ष अशोक पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा छत्तीसगढ़

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। राजनांदगांव जिला इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है।

योजनागत उपलब्धियों के आधार पर राजनांदगांव प्रदेश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। जिले में अब तक योजना के अंतर्गत 8 हजार 256 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4 हजार 120 हितग्राहियों के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि शेष प्रकरणों में दस्तावेजों के सत्यापन, संयंत्र स्थापना एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। योजना के तहत अब तक 3 हजार 205 हितग्राहियों को शासन की ओर से सब्सिडी का लाभ मिल चुका है।

वहीं 1 हजार 155 परिवारों का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। ये परिवार अब अपनी आवश्यकता के अनुरूप सौर ऊर्जा का उपयोग कर बिजली खर्च में उल्लेखनीय बचत कर रहे हैं। कई हितग्राही अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में भेजकर ऊर्जा उत्पादन में भी भागीदार बन रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले की सभी जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से पीएम सूर्य सभा आयोजित की जा रही है।

खुली नालियां बनीं जानलेवा, निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, बारिश में हादसों का खतरा बढ़ा

तुरंत कवरिंग और मरम्मत कार्य करने की मांग, निगम आयुक्त ने दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

खुर्सीपार जोन 4, सेक्टर 11, जोन 3 और मदर टेरेसा नगर सहित भिलाई के कई वार्डों में खुली और टूटी-फूटी पक्की नालियों के कारण आमजन की जान जोखिम में पड़ गई है। इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

बारिश में बढ़ गया हादसों का खतरा

ज्ञापन में कहा गया है कि शहर के व्यस्ततम मुख्य मार्गों और वार्डों के चौराहों-मोड़ पर गलत तरीके से बनाई गई नालियां अब जानलेवा साबित हो रही हैं। विशेषकर बारिश के मौसम में जलभराव के कारण नालियों के किनारे के गड्ढे छिप जाते हैं। ढक्कन विहीन या टूटी नालियों के कारण कई दोपहिया वाहन चालक वाहन सहित गिरकर घायल हो चुके हैं।

सड़क से सटे टर्निंग मोड़ और छोटी पुलियों के अगल-बगल दीवार न होने से राहगीरों को आने-जाने में भारी दिक्कत हो रही है। रात के समय और बरसात में नाली की गहराई का अंदाजा न लग पाने के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है।

प्रमुख हादसा संभावित स्थान

ज्ञापन में कई संवेदनशील जगहों का जिक्र किया गया है:

वार्ड 40 छावनी: इंडस्ट्रीज एरिया से बापू नगर, तीन तालाब की ओर जाने वाली सड़क के साथ पुलिया एक साल पहले धंसकर 10 फीट गहरी हो गई है।

वार्ड 43 राजीव नगर: मोची मोहल्ला से आने-जाने वाली सड़क पर भी इसी तरह की स्थिति है।

वार्ड 32 वैकुंठ धाम: गार्डन पानी टंकी की तरफ वाधवा को-ऑपरेटिव के पहले चौराहे पर पानी टैंकर के मुड़ते समय खुली नाली में कई स्कूली बच्चे गिर चुके हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना जान जोखिम में डालकर इस मार्ग से गुजरना पड़ रहा है।

त्वरित बैरिकेडिंग और कवरिंग की मांग

नागरिकों ने आयुक्त से मांग की है कि शहर के मुख्य आवाजाही वाले संवेदनशील स्थानों पर तुरंत बैरिकेडिंग की जाए और खुली नालियों की मरम्मत कर उन्हें कवर किया जाए। समय रहते कार्रवाई न होने पर किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका जताई गई है।

ज्ञापन में कहा गया कि "आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है।" नागरिकों ने प्रशासन से बारिश से पहले ठोस कदम उठाने की अपील की है ताकि भविष्य में होने वाले हादसों को टाला जा सके।

शहर के आवारा कुत्तों और पशुओं पर कार्यवाही करें सरकार - कुसुम दुबे

जीव जंतु कल्याण बोर्ड छ ग शासन को पत्र प्रेषित

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

शहर जिला कांग्रेस कमेटी की महामंत्री एवं अधिवक्ता कुसुम दुबे ने शहर में आवारा कुत्तों की बाढ़ एवं गौमाताओं के सड़कों पर बैठे रहने पर हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए जीव जंतु कल्याण बोर्ड छग शासन के क्रियाशील उपाध्यक्ष आलोक चंद्राकर जी को पत्र लिखकर सम्यक कार्यवाही की मांग की है।

महामंत्री एवं अधिवक्ता कुसुम दुबे ने बताई की शहर के सभी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की जिस प्रकार से बाढ़ आ गई है उसे आए दिन कुत्ता काटने की घटना एवं कुत्तों के हमले की बातें लगातार सामने आ रही है और तो और शहर के सीमा अंतर्गत वार्डों में रात में सैकड़ों कुत्ते की भयावह झुंड को देखकर आम जनता भयभीत जीवन जीने को विवश है ऐसी स्थिति में प्रशासन को आवारा कुत्तों के धर पकड़ की मुहिम में तेजी लाकर आम जनता को राहत देने की मजबूत कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर गौमाताए लगातार सड़कों में बैठी रहती हैं जिसके कारण भी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं और गौ माताएं भी चोटिल हो रही हैं जिससे जनभावना भी आहतत होती है ऐसी दशा में यदि किसी व्यक्ति विशेष के गाय सड़क पर बैठी है तो उन्हें सख्त चेतावनी दी जाए कि वह गौ माताएं की संरक्षण की जवाबदेही सुनिश्चित करें अन्यथा कार्यवाही की जाएगी और इन दोनों गम्भीर मामले को लेकर छत्तीसगढ़ शासन जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सजग उपाध्यक्ष आलोक चंद्राकर जी को संबोधित करते हुए राज्य स्तर से विशेष कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित की गई है उस पत्र को तत्काल श्री चंद्राकर ने विभाग प्रमुख को कार्यवाही कर अवगत कराने का निर्देश दिया है ताकि राज्य शासन स्तर से उचित और सम्यक कार्यवाही कर मानव जीवन को, गौ माताओ को सुरक्षित किया जा सके और आवारा कुत्तों के भयावह झुंड, हमले सहित बच्चे,आम जनता को भय मुक्त किया जा सके ।

रायपुर में 28 जुलाई को बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे सचिन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट 28 जुलाई को रायपुर दौरे पर आएंगे। माना जा रहा है कि वे नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस के चल रहे प्रदर्शन में शामिल होंगे। हालांकि, उनके दौरे की अवधि और अन्य कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पायलट के दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठकों की भी संभावना है। हाल के दिनों में प्रदेश कांग्रेस के संगठन में बदलाव और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों के बीच इस दौरे को अहम माना जा रहा है। इससे पहले 25 जून को सचिन पायलट रायपुर आए थे। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया था और मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा था।

रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि भाजपा को कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की चिंता छोड़कर अपनी सरकार और संगठन की अंदरूनी खींचतान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है और नए जिला अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पायलट ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी की सोच के अनुरूप कांग्रेस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के अभियान में जुटी है।

GOSWWAMI
FLEX PRINTING
ADVERTIZER
भिलाई में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा
Hoardings Flex Banner Vinyl Printing
One Way Vision Glow Sign Board
93290-13334, 74711-15735
goswamiflex@gmail.com
Address - 3rd Floor Shop No-1, Arora Tower, M.C. Market

अर्चना
फ्लाई ऐश ब्रिक्स
निर्माता एवं विक्रेता
हैवी इंडस्ट्रीयल एरिया, भिलाई
8 इंच एवं 9 इंच में उपलब्ध है।
संपर्क करें
9329960605, 9827160605, 9098639991

Baked by Suhani
Premium Homemade Cakes & Desserts
Birthday Cakes
Anniversary Cakes
Custom Theme Cakes
Serving Bhilai & Durg
Order Now:
@baked.by.suhani
M0.6263734520

10वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पास छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण
नौकरी में सहायक
प्रवेश प्रारंभ सत्र 2026-2027
निजी कंपनियां जैसे पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत नौकरियाँ मिलती है।
प्रशिक्षण शुल्क में विशेष छूट
सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण में प्रवेश प्रारंभ

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	क्र.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी	5.	पी. जी. कोर्स व्यावसायिक सेफ्टी, स्वास्थ्य व पर्यावरण मैनेजमेंट सिस्टम
2.	इंडस्ट्रियल सेफ्टी / पी. जी. इंडस्ट्रियल सेफ्टी	6.	हैल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर
3.	बी.एस.सी. इन फायर सेफ्टी	7.	सब- फायर ऑफिसर
4.	पी. जी. कोर्स फायर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी	8.	सर्टिफिकेट इन फायरमैन-इंडस्ट्रियल सेफ्टी

(An Authorized Training Centre of AEERO)
फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
(मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षण संस्थान)
कैंपस :- इंदिरा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़
ADMISSION HELPLINE: 7697212782

BA
BCA
BCom
BBA
BSc
PGDCA
MSc CHEMISTRY
MSc BIOTECHNOLOGY
MSc BOTANY
MSc ZOOLOGY
MSc COMPUTER Sc
MSc MATHS
MA ENGLISH
MCom
BLib
MLib
DCA
MA CHHATTISGARHI
Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg
SAI COLLEGE
Street-69, Sector-6, Bhilai
70248 86996
99770 01027
Deepak Advertisers

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100